32

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2022/* फाल्गुन, *1943* (शक)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

21.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2022/* फाल्गुन, *1943* (शक)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
4. श्री कार्ती पी. चिदंबरम
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री जयदेव गल्ला
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री संतोष पान्डेय
13. श्री पी. आर. नटराजन
14. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
15. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
16. श्री संजय सेठ
17. श्री गणेश सिंह
18. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
21. **रिक्त**

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. श्री जॉन ब्रिटास
24. डॉ. सुभाष चन्द्र
25. श्री वाई. एस. चौधरी
26. श्री रंजन गोगोई
27. श्री सुरेश गोपी
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफ़र इस्लाम
30. जवाहर सरकार
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री वाई. एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	निदेशक
3. श्री शांगरिसो जिमिक	-	उप सचिव

समिति का गठन समाचार भाग - दो का पैरा संख्या 3184 दिनांक 9 अक्टूबर, 2021 के तहत 13 सितंबर, 2021 को किया गया।

समिति शाखा-1 द्वारा जारी समाचार भाग - दो पैरा संख्या 3293 दिनांक 23 नवंबर, 2021 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का नाम बदल कर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया है।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सभापति (22-2021) के (दूरसंचार विभाग) समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर यह (23-2022)बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

.2 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति सितंबर 13 का गठन (22-2021) में यथा .ड331 को हुआ। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2021 विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना /निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय त करना है।और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तु

.3 समितिि ने संचार मंत्रालय के लिए 23-2022 बंधित वर्षसे सं (दूरसंचार विभाग) 0 अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे9 फरवरी,2022 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने लिया।के प्रतिनिधियों का साक्ष्य (दूरसंचार विभाग) को संचार मंत्रालय 24.02.2022

.4 16 03.2022.को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचारोपरांत स्वीकृत किया गया।

.5 के अधिकारियों को समिति के समक्ष (दूरसंचार विभाग) समिति संचार मंत्रालय उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई वाद देती है।सूचना देने के लिए धन्य

.6 समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियें द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देती है।

7. णियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्प दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।-भाग

नई दिल्ली;
16 मार्च, 2022
25 फाल्गुन, 1943 (शक(

शशि थरूर .डॉ
सभापति,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

एक. <u>परिचय</u>

दूरसंचार विभाग (डीओटी) अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार नीति; लाइसेंस प्रदान करने, तार, टेलीफोन, दूरसंचार वायरलेस डाटा से संबंधित मामलों का समन्वय करने; दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानक संवर्धन, दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी); और इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। दूरसंचार विभाग अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके रेडियो संचार के क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। दूरसंचार विभाग पूरे देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखकर बेतार विनियामक उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

2. दूरसंचार को जनता के सशक्तिकरण के माध्यम से विकास करने और गरीबी को कम करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विश्व भर में मान्यता प्रदान की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2030 की धारणीय विकास कार्यसूची के धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक मुख्य घटक है, जिसमें इसकी बढ़ती हुई पहुंच, बेहतर नेटवर्क और उन साधनों और समाधानों का उल्लेख किया गया है जो पद्धतियों के अंकीकरण (डिजिटाईजेशन), विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में कृषि, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वतपूर्ण क्षेत्रों की प्रक्रियाओं और संपर्कों को बढ़ाते हैं। घोर महामारी की अवधि के दौरान विभाग ने कई पहलें की जैसे निर्बाध कनेक्टिविटी, निर्बाध सेवाएं, घर से काम करना, कहीं से भी काम करना और ऑनलाइन कक्षाएं।

3. दूरसंचार नेटवर्क उद्योग है जिसमें नए प्रयोक्ता नेटवर्क को व्यापक बनाकर वर्तमान प्रयोक्ताओं के लिए सकारात्मक गुणवत्ता सृजित करते हैं। सूचना किसी भी अर्थव्यवस्था की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है और यह सकारात्मक आर्थिक गुणवत्ता से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। सूचना प्राप्त करने की लागत में कमी करके दूरसंचार ट्रांजेक्शन लागतों में कमी आती है, अतिरिक्त ट्रांजेक्शन के लिए अवसर सृजित होते हैं और इससे इसलिए आर्थिक कुशलता और विकास में योगदान मिलता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए ट्रांजेक्शन लागतों में कटौती करना दूरसंचार का प्रमुख योगदान है। सूचना और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में

सूचना को एक्सेस, प्रोसेस और प्रसार करने की सुविधाएं भूमि, श्रम और पूंजी के रूप में महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है।

4. उच्च आर्थिक विकास ने वर्तमान और नई दूरसंचार सेवाओं की मांग सृजित की है जिससे इस क्षेत्र का विकास हुआ है जबकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वयं आवश्यक निवेश संसाधन उपलब्ध कराती है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उचित और अनुकूल नीतियों से दूरसंचार क्षेत्र का समर्थन किया है। नीतिगत पहलों के जरिए सरकार ने सेवा प्रदाताओं में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की है और निष्पक्ष एवं सक्रिय विनियामक फ्रेमवर्क ने दूरसंचार सेवाओं को किफायती बना दिया है और इससे देश के आम आदमी की पंहुच आसान बन गई है।

5. इस समय भारत टेलीफोन कनेक्शन के मामले में 1.19 बिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब भारत का मोबाइल सब्सक्रिप्शन सभी टेलीफोन सब्सक्रिप्शनों का लगभग 98% है।

दो. <u>संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदान मांगों (2021-22) के संबंध में समिति के तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति</u>

6. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदान मांगों (2021-22) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का तेइसवां प्रतिवेदन 10 मार्च, 2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। दूरसंचार विभाग ने 27 जुलाई, 2021 को तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किए। तेईसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उनतीसवां प्रतिवेदन 1 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 15 सिफारिशों में से 08 सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। समिति ने 04 सिफारिशों पर टिप्पणी की थी और 03 सिफारिशों के उत्तर अंतरिम प्रकृति के पाए गए थे जिन पर मंत्रालय से अंतिम उत्तर मांगे गए हैं। उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम विवरण को बाद में संसद के पटल पर रखा जाएगा।

तीन. <u>दूरसंचार बजट (2022-23)</u>

7. दूरसंचार विभाग ने 9 फरवरी, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मांग संख्या 13 प्रस्तुत की। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए राजस्व और पूंजी खंडों के

तहत वास्तविक, 2021-22 का प्रस्तावित, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक, राजस्व और पूंजी खंडों के तहत 2022-23 के दौरान प्रस्तावित और बीई का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख शीर्ष	2018-19 **वास्तविक**	2019-20 **वास्तविक**	2020-21 **वास्तविक**	2021-22 **प्रस्तावित**	2021-22 **बजट अनुमान**	2021-22 **संशोधित अनुमान**	2021-22 **वास्तविक (दिसम्बर 2021 तक)**	2022-23 **प्रस्तावित**	2022-23 **बजट अनुमान**
राजस्व खंड	24691.73	26392.44	45154.71	51587.71	41803.44	38380.04	22425.36	44843.94	32436.38
पूंजी खंड	4041.44	9634.49	8356.11	11755.61	31133.56	10670.17	6268.52	4990.97	63111.42
कुल अनुदान	**28733.17**	**36026.93**	**53510.82**	**63343.32**	**72937.00**	**49050.21**	**28693.88**	**49834.91**	**95547.80**

(ii) <u>राजस्व खंड</u>

8. दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार राजस्व खंड के तहत व्यय का शीर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

)करोड़ रुपये में(

क्र.सं.	**शीर्ष का नाम**	**प्रमुख शीर्ष**	**बजट अनुमान 2021-22**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**व्यय दिसंबर, 2021 तक**
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	789.91	869.15	527.90
2	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	15350.00	16374.16	11961.56
3	श्रम रोजगार और कौशल विकास	2230	4.09	4.10	4.09
4(क)	वायरलेस और योजना समन्वय	3275	13.99	15.80	12.56
(ख)	निगरानी सेवाएं	3275	40.50	40.50	31.13

(ग)	यूएसओएफ के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा	3275	9000.00	8300.00	3340.19
(घ)	रिजर्व फंड में अंतरण	3275	9000.00	8300.00	3340.19
(ड.)	टीडीआईपी	3275	9.00	6.45	1.76
(च)	एमटीएनएल बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान	3275	383.21	383.57	347.95
(छ)	श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण	3275	1.00	0.00	0.00
(ज)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के लिए विशेष सहायता	3275	2.5	2.5	0.00
(झ)	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3275	60.00	30.00	25.88
(ञ)	सी-डॉट	3275	325.70	400.00	272.92
(ट)	आईटीआई, बैंगलोर	3275	0.01	0.00	0.00
(ठ)	ट्राई - ट्राई जनरल फंड में अंतरण	3275	100.00	92.00	60.00
(ड)	टीडीसैट	3275	18.50	17.81	12.42
(ढ)	प्रशिक्षण (एनआईसीएफ और एनटीआईपीआरआईटी)	3275	26.03	5.00	3.20
(ण)	दूरसंचार क्षेत्र के नवाचार और भावी प्रौद्योगिकी के इनक्यूबेशन के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम का प्रावधान	3275	5.00	9.00	4.15
(त)	4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी की मंजूरी	3275	3674.00	0.00	0.00
(थ)	बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले कर्मचारियों के लिए वृद्धिशील पेंशन	3275	3000.00	3530	2479.46
	कुल राजस्व खंड (सकल)		**41803.44**	**38380.04**	**22425.36**

9. प्रस्तावित राशि 44843.94 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 32436.38 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो प्रस्तावित राशि से 12,407.56 करोड़ रुपये कम है। विभाग ने बताया है कि यूएसओएफ की भारतनेट स्कीम के लिए आवंटन पहले राजस्व खंड के तहत था। ब.अ .वर्ष 23-2022से इसे अनुदान के पूंजी खंड में अंतरित कर दिया गया है। तथापि वित्त मंत्रालय को ब.अ 23-2022 .प्रस्ताव भेजते समय भारतनेट के

लिए आवंटन राजस्व खंड के तहत प्रस्तावित किया गया था। ब.अ. में आवंटित राशि राजस्व खंड के तहत प्रस्तावित राशि से काफी कम प्रतीत होने की मुख्य वजह यही है। यूएसओएफ)भारतनेट के अलावा (और पीएलआई जैसी प्रमुख स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय ने विभाग द्वारा प्रस्तावित राशि आवंटित की है।

10. राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय के संबंध में विभाग ने सूचित किया है कि 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार 31,547.03 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शेष राशि विशेष रूप से यूएसओएफ जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग की जाएगी।

(iiii) <u>पूंजी खंड</u>

11. 21 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार पूंजी खंड के तहत व्यय का शीर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**शीर्ष का नाम**	**प्रमुख शीर्ष**	**ब.अ. 2021-22**	**सं.अ. 2021-22**	**दिसम्बर'21 तक का व्यय**
1	आईटीआई पुनरुद्धार(इक्विटी निवेश)	4859	80.00	80.00	0.00
2	बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश	5275	20410.00	0.00	0.00
3	निदेशालय एवं प्रशासन प्रमुख निर्माण कार्य		0.01	0.01	0.00
4	डबल्यूएमओ प्रमुख निर्माण कार्य		5.50	6.70	3.28
5	डब्ल्यूपीसी		0.01	0.01	0.00
6	निगरानी सेवाएं		3.05	3.65	0.28
7	डीएस के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क		5200.00	5200.00	3069.92
8	सीआरआईएफ को अंतरित धनराशि		5200.00	5200.00	3069.92
9	भारतनेट		0.00	0.00	0.00
10	रिजर्व निधि में अंतरण		0.00	0.00	0.00
1 1	वायरलेस सेट और उपकरण (टीईसी)		20.00	5.00	0.51
12	राष्ट्रीय संचार वित्त के लिए प्रशिक्षण संस्थान (एनआईसीएफ)		53.97	32.00	10.71
13	दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र		15.00	0.00	0.00

14	टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्ट)		23.00	16.00	0.00
15	केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)		13.00	12.00	0.00
16	स्वदेशी 5जी परीक्षण बिस्तर		0.01	1.80	0.90
17	ट्राई बिल्डिंग		110.00	113.00	113.00
18	सैटेलाइट गेटवे की स्थापना बीएसएनएल को सहायता		0.01	0.00	0.00
19	डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट प्रोजेक्ट		0.00	0.00	0.00
	कुल पूंजी खंड		**31133.56**	**10670.17**	**6268.52**

12. 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान (आरई) चरण में किए गए आवंटन में कटौती के संबंध में, विभाग ने बताया कि आवंटन में कमी मुख्य रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल में 4जी स्पेक्ट्रम के लिए 20,410 करोड़ रुपये की सीमा तक पूंजी को सरेंडर किए जाने के कारण है। इसके लिए बजट अनुमान (बीई) 2022-23 में प्रावधान किया गया है।

13. वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग द्वारा पूंजी खंड के अंतर्गत दिसंबर, 2021 तक 6268.52 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है, जो संशोधित अनुमान में आवंटित राशि से 4401.65 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमान 2021 की तुलना में पूंजीगत अनुभाग के तहत निधियों के उपयोग में कमी के कारणों के बारे में, विभाग ने बताया है कि दिनांक 28.02.2022 को पूंजी शीर्ष के अंतर्गत व्यय 6312.63 करोड़ रुपए है। यह उल्लेखनीय है कि सं.अ. 2021-22 में आवंटित राशि का 97% एनएफएस (रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क) के लिए है, जिसमें जारी की गई धनराशि की मात्रा आमतौर पर बड़ी होती है। उम्मीद है कि आवंटित राशि का इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग कर लिया जाएगा।

14. बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र, दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) जैसी योजनाओं के लिए धन के शून्य उपयोग को नोट करते हुए, समिति ने इन योजनाओं के तहत सुचारू कार्यान्वयन और निधियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में विभाग ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम हेतु पूंजी निवेश का प्रावधान सरेंडर कर दिया गया है क्योंकि बीएसएनएल को घरेलू उपकरणों के साथ 4जी

पीओसी (अवधारणा का साक्ष्य) शुरू करने के लिए कहा गया था और परिणामस्वरूपवर्ष 2021-22 में स्पेक्ट्रम आवंटन नहीं किया जा सकता है। टी-सर्ट (टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) और सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) के लिए सं.अ. 2021-22 में प्रावधान की गई लगभग पूरी राशि जारी कर दी गई है। दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र (टीटीएससीसी) स्कीम के संबंध में, एनसीसीएस, बेंगलुरु में 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड की स्थापना के लिए प्रस्तावित नई परियोजना के लिए ब.अ. 2021-22 के तहत धन का आवंटन मांगा गया था। हालांकि, सं.अ. 2021-22 में शून्य आवंटन मांगा गया था क्योंकि 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड के लिए परियोजना अनुमान विचाराधीन है।

चार. <u>सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)</u>

15. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार लाइसेंस शुल्क में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी शामिल है जो दूरसंचार लाइसेंसधारकों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5% की दर से ली जाती है। यूएएल के तहत एकत्र की गई निधि भारत की समेकित निधि में जाती है और यह गैर-व्यपगत है। यूएसओएफ को इस निधि का बहिर्गमन यूएसओएफ की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय प्रावधान के माध्यम से किया जाता है। यूएसओएफ की स्थापना के बाद अर्थात् वर्ष 2002-03 से 1,21,827.84 करोड़ रुपये की यूएएल राशि एकत्र की गई है। संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से प्राप्त 62,564.16 करोड़ रुपये की राशि के अंतिम आबंटन को संबंधित वर्षों में हेड 8235 जनरल एंड रिजर्व फंड-118 यूएसओ फंड को अंतरित कर दिया गया था और इस प्रकार यूएसओ फंड में किए गए समग्र आवंटन और अंतरण का उपयोग संबंधित वर्षों में किया गया है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार यूएसओ के तहत संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यूएएल राशि का शेष बकाया 59,263.68 करोड़ रुपये है। यूएसओएफ विभिन्न स्कीमों की पूर्ति हेतु अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान तैयार करता है और दूरसंचार विभाग की बजट शाखा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय को निधियों की आवश्यकता को अग्रेषित करता है। दूरसंचार विभाग की बजट शाखा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय से प्राप्त आबंटनों का उपयोग यूएसओएफ की अनुमानित योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

16. यूएसओएफ की विभिन्न योजनाओं के लिए 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, के दौरान प्रस्तावित, बजट अनुमान (बीई) के दौरान आवंटित, संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक उपयोग तथा 2022-23 के दौरान प्रस्तावित और बजट अनुमान (बीई) राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	10450.00	8350.00	8000.00	13250.00	9000.00
बजट अनुमान	10,000.00	8350.00	8000.00	9000.00	9000.00
संशोधित अनुमान	4788.22	3000.00	7200.00	8300.00	
वास्तविक	4788.22	2926.00*	7200.00	3340.68 (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	
संशोधित अनुमान से संबंधित प्रतिशत	**100%**	**100%**	**100%**	**40.24%**	

*वित्त मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 3000 करोड़ रूपए (भारतनेट के लिए 2000 करोड़ रूपए और अन्य यूएसओएफ स्कीमों के लिए 1000 करोड़ रूपए) संशोधित आवंटन के रूप में प्राप्त हुए थे जिसमें से अन्य शीर्षों में तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 74 करोड़ रूपए की राशि पुनर्विनियोजित की गई थी।

17. जब समिति ने 2021-22 के दौरान बीई और आरई के बीच भिन्नता के कारणों को जानना चाहा, तो विभाग ने समिति को बताया है कि वर्ष 22-2021के लिए बजट अनुमान में 9000करोड़ रूपए)भारतनेट के लिए 2000करोड़ रूपए और अन्य यूएसओएफ स्कीमों के लिए 1000करोड़ रूपए (की राशि प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 22-2021के लिए 9000करोड़ रूपए के प्रस्तावित संशोधित अनुमान की तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा 7000)करोड़ रूपए भारतनेट के लिए और 1300करोड़ रूपए अन्य यूएसओएफ स्कीमों के लिए 8300 (करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 22-2021के दौरान भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य प्राप्ति की तुलना में धीमी थी। चरण-II का कार्य व्यापकरूप से 8राज्यों)राज्य

आधारित मॉडल के तहत लगभग 65000ग्राम पंचायतें (और बीएसएनएल) सीपीएसयू आधारित मॉडल में 23000ग्राम पंचायतें (पर निर्भर था। बीएसएनएल की अपने आंतरिक मुद्दों और वित्तीय कठिनाइयों के कारण क्षमता प्रभावित रही थी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में राज्य आधारित मॉडल के तहत प्रगति कोविड संबंधी प्रतिबंधों, समय पर संबंधित मंजूरी और अनुमोदन मिलने में विलम्ब तथा राज्यों द्वारा परियोजना के कमजोर कार्यान्वयन के कारण अपेक्षाकृत धीमी रही है।

18. यूएसओएफ में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद वर्ष 2021-22 के दौरान ब.अ. से सं.अ. राशि को 700 करोड़ रुपये तक कम करने के कारणों के बारे में विभाग ने बताया है कि यूएसओएफ द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान के रूप में 9000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे, जिसके सापेक्ष में वित्त मंत्रालय से 8300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न यूएसओएफ स्कीमों के तहत खर्च को पूरा करने के लिए धन पर्याप्त है।

19. निधियों के उपयोग की गति को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के संबंध में, विभाग ने बताया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान भारतनेट चरण- II के कार्यान्वयन की प्रारंभिक गति लक्ष्य की तुलना में धीमी थी। चरण- II का काम काफी हद तक आठ राज्यों (राज्य आधारित मॉडल के तहत लगभग 65000 ग्राम पंचायत) और बीएसएनएल (सीपीएसयू आधारित मॉडल के तहत लगभग 23000 ग्राम पंचायत) पर निर्भर है। कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण मंजूरी प्राप्त करने आदि में कार्यान्वयन एजेंसियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालाँकि यूएसओएफ़/बीबीएनएल द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें, समस्या समाधान के लिए प्रशासनिक निर्णयों को सूचित करने और परियोजना कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे काम की गति में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा फरवरी, 2022 तक लगभग 6450 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया है, जो वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सं.अ. का लगभग 78% है। शेष निधि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक किए जाने की उम्मीद है।

20. विभाग ने आगे बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यूएसओएफ के तहत निम्नलिखित योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है:

(i) भारतनेट देशभर के सभी 6लाख गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना)सीटीडीपी -(राष्ट्रीय राजमार्गों सहित मेघालय और शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरसंचार सेवा से वंचित गांवों में 4जी कनेक्टिविटी का प्रावधान।

(iii) द्वीप समूह के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना -कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन केबल बिछाना और अंडमान एवं निकोबार में मोबाइल कनेक्टिविटी।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों के मोबाइल सेवा से वंचित 354गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए स्कीम।

(v) आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं के लिए स्कीम।

(vi) वामपंथी उग्रवाद)एलडब्ल्यूई (से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए स्कीम-चरण-। में 4जी में उन्नयन और चरण-II में 4जी सेवाओं का प्रावधान।

(i) भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति

21. भारतनेट विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है जिसका कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों)लगभग 2.6लाख (में चरणबद्ध आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भारतनेट के दोनों चरण-। और चरण-II के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 42, 068करोड़ रूपए की कुल राशि)जीएसटी एवं लेवी को छोड़कर (अनुमोदित की गई है। अब परियोजना के कार्यक्षेत्र को बसे हुए सभी गांवों तक विस्तारित कर दिया गया है।

22. 2021-22 के दौरान प्रस्तावित, बीई, आरई और वास्तविक तथा 2022-23 के दौरान प्रस्तावित और बीई निम्नानुसार हैं:

करोड़ रु. में

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रस्तावित	8000.00	6000.00	6000.00	10000.00	7000.00

बजट अनुमान	8175.00	6000.00	6000.00	7000.00	7000.00
संशोधित अनुमान	4145.54	2000.00* (1657.74 करोड़ रुपये के रूप में पुन: विनियोजित)	5500.00 (5919.79 के रूप में पुन: विनियोजित)	7000.00	-
वास्तविक	4145.54	1657.74	5919.79	2876.28	-
संशोधित अनुमान के संदर्भ में %	100%	100%	100%	41.08%	-

(ii) **<u>भारतनेट चरण- I का कार्यान्वयन और स्थिति</u>**

23. चरण-I के कार्यक्षेत्र को संशोधित करके 1,20,314 कर दिया गया था क्योंकि पूर्वोत्तर की लगभग 3000 ग्राम पंचायतें जिनमें पहले कार्यान्वयन रेलटेल द्वारा किया जा रहा था, वे पीपीपी मॉडल के तहत प्रस्तावित हैं और कुछ ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। दिनांक 09.01.2022 की स्थिति के अनुसार कुल 1,18,946 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने के लिए लगभग 3,09,159 कि.मी. की भूमिगत ओएफसी बिछाई गई है। भारतनेट चरण-I की स्थिति (दिनांक 09.01.2022 की स्थिति के अनुसार) का ब्यौरा निम्नानुसार है-

सीपीएसयू	**चरण-I में योजनाबद्ध ग्राम पंचायतें**	**बिछाई गई ओएफसी (कि.मी.)**	**सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतें**
बीएसएनएल	101780	250521	100843
रेलटेल	8002	26928	7820
पीजीसीआईएल	10407	31649	10269
बीबीएनएल (बीएसएनएल से डाइवर्टेड)	125	61	14
कुल	**120314**	**309159**	**118946**

(iii) <u>भारतनेट चरण-II</u>

24. मंत्रिमंडल ने चरण-I के कार्यान्वयन अनुभव के आधार पर दिनांक 19 जुलाई, 2017 को भारतनेट के लिए संशोधित कार्यनीति अनुमोदित की थी और इसे डिजिटल भारत विजन के अनुरूप कर दिया था। संशोधित कार्यनीति से ग्राम पंचायतों (जीपी) को संचार सेवा से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल मीडिया मिश्रण (ओएफसी/रेडियो सेटेलाइट) उपलब्ध हुआ। इस कार्यक्षेत्र में अनेक मॉडलों यथा-राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू मॉडल आदि के माध्यम से कार्यान्वयन किए जाने हेतु ग्राम पंचायतों और ब्लॉक के बीच नया फाइबर बिछाते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 जीबीपीएस बैण्डविड्थ (वायर मीडिया पर) तक का प्रावधान शामिल है। चरण-II कार्यान्वयनाधीन है और 09.01.2022 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार हैं-

कार्यान्वयन मॉडल	**योजनाबद्ध ग्राम पंचायतें**	**बिछाई गई ओएफसी (कि.मी.)**	**सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतें**
राज्य आधारित मॉडल	65559	163361	27545
बीएसएनएल	27025	67206	11895
निजी आधारित मॉडल	7382	22755	7356
सेटेलाइट	5575	-	4289
राज्य आधारित मॉडल में नई सृजित ग्राम	2844	-	-
कुल	**108385**	**253322**	**51085**

(iv) <u>भारतनेट नेटवर्क का उपयोग</u>

25. भारतनेट चरण-I की लगभग 1.20 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.10 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सेवाओं के प्रावधान का कार्य सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विशिष्ट प्रयोजन साधन) को और लगभग 10,000 ग्राम पंचायतों में राजस्थान सरकार/राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. (आरआईएसएल) आदि को सौंपा गया है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) को देशभर में वाई-फाई सेवाओं के प्रावधान हेतु सौंपी गई लगभग 1.10

लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 77000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में 5 सरकारी संस्थाओं में एफटीटीएच कनेक्शनों का प्रावधान कर दिया गया है। उपयोग की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क. प्रयुक्त निधियां : 31.01.2022 तक 30885.31 करोड़ रुपये
ख. वाई-फाई संस्थापित ग्राम पंचायतें 1 :,04, 259
ग. एफटीटीएच कनेक्शन 1 :,89, 050
घ. पट्टे पर दिया गया डार्क फाइबर 34 :, 514कि.मी .
ङ. भारतनेट बैंडविड्थ को पट्टे पर दिया जाना 4 :, 075जीबीपीएस
च. डेटा उपयोग : दिसम्बर 2021के दौरान 5, 030टीबी डेटा

26. 1.10 लाख ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) और राजस्थान में 10,000 ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के कार्य-निष्पादन की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि सीएससी-एसपीवी और आरआईएसएल द्वारा ग्राम पंचायतों में कुल 94,268 और 8034 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। शेष ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार करने के बाद चरण-। की शेष ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाने की परिकल्पना की गई है।

27. बीबीएनएल को ब्लॉक से जीपी तक मध्य-मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक अधिदेश के साथ बनाया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि सेवा प्रदाता डार्क फाइबर लीज पर और ऑप्टिकल बैंडविड्थ बीबीएनएल से लेगा। हालांकि जुलाई, 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2016 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। वर्ष 2017 में सीएससी-एसपीवी द्वारा 5000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। तब से ग्राम पंचायत स्तर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। चरण-I के अंतर्गत कवर की गई ग्राम पंचायतों में वाई-फाई अभिगम बिंदु प्रदान करने का कार्य मुख्यत सीएससी-एसपीवी द्वारा यूएसओएफ से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। सीएससी-एसपीवी के अलावा राजस्थान की 10 हजार ग्राम पंचायतों में राजस्थान सरकार कार्य कर रही है। कुछ राज्य सरकारें राज्य वित्तपोषण के माध्यम से ग्राम पंचायतों में वाई-फाई भी प्रदान कर रही हैं। सीएससी-एसपीवी को चरण-I की 77115 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक

में 5 सरकारी संस्थानों को एफटीटीएच कनेक्शनों के प्रावधान के लिए वीजीएफ भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएससी को चरण-II की 2692 ग्राम पंचायतों और बिहार के 36744 गांवों में से प्रत्येक में 1 वाई-फाई और 5 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94800 सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, राशन की दुकानें, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डाकघर आदि को सीएससी-एसपीवी द्वारा पहले ही जोड़ा जा चुका है।

28. विभाग ने आगे बताया कि चरण-II में संशोधित कार्यनीति के तहत भारतनेट अवसंरचना के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्यान्वयन एजेंसियां न केवल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी बल्कि भारतनेट के तहत सृजित अवसंरचना के प्रचालन, रखरखाव और उपयोग के लिए भी उत्तरदायी होंगी। राज्य आधारित मॉडल में भारतनेट चरण-II में उपयोग का कार्य राज्यों को सौंपा गया है। स्वान, ई-गवर्नेंस और अन्य सेवाओं के लिए नेटवर्क के उपयोग के लिए राज्य सरकारों का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 16424 ग्राम पंचायतों में अपने स्वान का ग्राम पंचायतों तक विस्तार करने के लिए भारतनेट का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में एफटीटीएच कनेक्शनों के प्रावधान के लिए आईएसपी के साथ राजस्व साझेदारी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक आईएसपी के साथ 54 राजस्व शेयर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में एफटीटीएच कनेक्शन का प्रावधान बढ़ेगा।

29. भारतनेट के कार्यान्वयन और उपयोग के बारे में और विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

"सर, जैसा कि आप जानते हैं, भारतनेट को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाना था जो अब पूरा हो गया है। दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। पहले चरण में, 1.18 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा योग्य तैयार किया गया है और चरण II में अन्य 50,000 ग्राम पंचायतों को सेवा योग्य तैयार किया गया है। कुल आंकड़ा लगभग 1.70 लाख ग्राम पंचायतों का बनता है। ....xxxx.....जहां तक उपयोग का संबंध है, 1.04 लाख ग्राम पंचायतों को वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स के साथ जोड़ा गया हैं और दिसंबर, 2021 में प्रति माह लगभग 5,000 टीबी मूल्य के डेटा की खपत का उल्लेख किया गया है, जिसे हम आने वाले दिनों में अधिक से अधिक उपयोग मॉडल के आकार लेने के साथ

बढ़ने की उम्मीद करते हैं। लगभग 34,000 किलोमीटर गहरे फाइबर को पट्टे पर दिया गया है और लगभग 4,000 जीबी बैंडविड्थ प्रोविजनिंग की गई है। जैसा कि मैंने बताया है, 45 राजस्व-साझाकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और हर दिन, हम नागरिकों और परिवारों के लिए नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अंतिम मील पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और लाइसेंसधारकों के साथ अधिक समझौतों कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी संस्थानों को भी अब बीबीएनएल स्तर पर एक एकल-खिड़की प्रणाली बनाकर एक मिशन मोड पर शुरू किया जा रहा है ताकि केंद्रीय विभाग, जिनके पास फील्ड संरचनाएं हैं, हमारे साथ उन संस्थानों की संख्या के आंकड़े साझा कर रहे हैं जहां वे भारतनेट कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे चैनल पार्टनर के माध्यम से, हम उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहते हैं।"

(v) <u>6 लाख गांवों को जोड़ने के लिए भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति</u>

30. दिनांक 30.06.2021को ,केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त, 2023 तक देश के 16राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन कार्यनीति को मंजूरी दी। भारतनेट को अब सभी बसे हुए गांवों में विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। संशोधित कार्यनीति में छूटग्राही/निजी सेवा प्रदाता द्वारा निर्माण ,उन्नयन , प्रचालन ,रखरखाव और भारतनेट नेटवर्क का उपयोग शामिल है ,जिनका चयन वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त पीपीपी मॉडल के लिए स्वीकृत अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर निधि 16राज्यों के लिए 19,041करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के तहत आने वाले राज्य केरल ,कर्नाटक ,राजस्थान ,हिमाचल प्रदेश , पंजाब ,हरियाणा ,उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,पश्चिम बंगाल ,असम ,मेघालय ,मणिपुर ,मिजोरम, त्रिपुरा ,नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं । इसमें ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61लाख गांवों को कवर किया जाएगा। 16राज्यों में पीपीपी मॉडल के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव अनुरोध)आरएफपी (जारी किया गया है।

31. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने के लिए निम्न कार्रवाई की गई है:

i. राज्य आधारित मॉडल

राज्य आधारित मॉडल 8)राज्य (के तहत कार्य की प्रगति भारतनेट चरण-II में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। दूरसंचार विभाग बसे हुए सभी गांवों में कनेक्टिविटी और चरण-। की

ग्राम पंचायतों के उन्नयन सहित कार्य में तेजी लाने के लिए इन राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। राज्यों को पीपीपी मॉडल अथवा ईपीसी मॉडल के माध्यम से कार्य करने का विकल्प दिया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल से उक्त आठ राज्यों में बसे हुए सभी गांवों और चरण-। की ग्राम पंचायतों के उन्नयन के लिए आवश्यक अनुमोदन अलग से मांगा जाएगा।

ii. गोवा और उत्तराखंड

गोवा और उत्तराखंड राज्यों से प्राप्त सहमति के आधार पर इन राज्यों को पीपीपी मॉडल में शामिल किया जाना है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल से आवश्यक अनुमोदन की मांग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

iii. बिहार में ग्राम पंचायत/ग्राम कनेक्टिवि :

इस राज्य में सीएससी-एसपीवी के माध्यम से सार्वजनिक संस्थाओं में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट और 5एफटीटीएच कनेक्शनों के प्रावधान सहित राज्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के ग्राम पंचायतों से सभी गांवों तक विस्तार के लिए एक प्रायोगिक मॉडल का कार्यान्वयन चल रहा है।

iv. संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम कनेक्टिविटी:

जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, पुद्दुचेरी तथा सिक्किम राज्य में ग्राम पंचायत से ग्राम स्तर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का कार्य-निष्पादन विचाराधीन है।

32. 6 लाख गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, प्रशासक, यूएसओएफ ने साक्ष्यों के दौरान बताया कि:

"सर, अब आगे का रास्ता यह है कि हम भारतनेट के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे पास तीन अलग-अलग मॉडल हैं। आठ राज्यों को अब राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के साथ कवर किया जा रहा है जहां एसपीवी के माध्यम से राज्य सरकारें वास्तव में ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं। ऐसे 16 राज्य हैं जिनमें हमने भारतनेट नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल शुरू किया था। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे। महोदय, ओएंडएम हमारे लिए एक अन्य प्रमुख क्षेत्र बनने जा रहा है क्योंकि हमने पहले ही लगभग 55 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा दिया है जिसके लिए निरंतर रखरखाव और ध्यान की आवश्यकता होगी। तत्पश्चात्, मौजूदा नेटवर्क के उपयोग के संबंध में, जो अतीत में चिंता का कारण रहा है, अब उस पर भी ध्यान केन्द्रित

किया गया है और अंतिम-मील इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ विभिन्न राजस्व-साझाकरण व्यवस्थाओं में प्रवेश किया गया है क्योंकि अब भारतनेट को एक मध्य-मील नेटवर्क होने के नाते गांवों में अंतिम-मील सेवा प्रदाताओं तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए अंतिम मील सेवा प्रदाताओं से जुड़ने की आवश्यकता है। अब हम दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की खोज के विकल्प का भी उपयोग कर रहे हैं जहां ऑप्टिकल फाइबर बिछाना एक व्यवहार्यता नहीं हो सकती है, जिसमें रेडियो, वी-सैट के साथ-साथ अन्य नई प्रौद्योगिकियां भी शामिल हो सकती हैं। महोदय, यह समग्र रूप से इस बात का एक स्नैपशॉट है कि देश के छह लाख से अधिक गांवों को अब भारतनेट के अंतर्गत कैसे शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने जून 2021 में अपने फैसले में इसे ग्राम पंचायतों से आगे गांवों तक भी विस्तारित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जैसा कि मैंने समझाया, हम पीपीपी, राज्य के नेतृत्व वाले और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नेतृत्व वाले मॉडलों सहित कई मॉडलों का उपयोग करेंगे, ताकि देश के सभी गांवों को चरणों में कवर किया जा सके।"

33. प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) पर आई प्रतिक्रिया और सभी 6 लाख गांवों को जोड़ने के लिए समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया है कि अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) दिनांक 27.01.2022 को खोला गया था। बोलियों के लिए कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है और भारतनेट के भाग के रूप में संशोधित मॉडल तैयार किया जा रहा है तथा वर्ष 2025 तक रॉल-आऊट किए जाने की संभावना है।

(vi) <u>आकांक्षी जिला योजना</u>

(क) <u>राजस्थान ,उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश) आकांक्षी जिला गांव 502, बिहार(</u>

34. 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए चार राज्यों (अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के 112 आकांक्षी जिलों में 502 सेवा से वंचित गांवों के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और मार्च, 2021 में निविदा प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, राजस्थान के लिए मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और बिहार के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को कार्य सौंपा गया है। परियोजना की कुल लागत 421.65 करोड़ रुपये है जिसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण कार्य

और टावर की संस्थापना का कार्य चल रह है। सेवा से वंचित गांवों की राज्यवार सूची इस प्रकार है-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	आकांक्षी जिलों की संख्या	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या
1	बिहार	5	80
2	मध्य प्रदेश	8	205
3	राजस्थान	5	195
4	उत्तर प्रदेश	6	22
	कुल	**24**	**502**

(ख) <u>शेष 7,287आकांक्षी जिलों के गांव)आंध्र प्रदेश ,छत्तीसगढ़ ,झारखंड ,महाराष्ट्र और ओडिशा(</u>

35. मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 17.11.2021को 7,287अनकवर्ड गांवों के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई थी ,जिसमें 6,466करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आंध्र प्रदेश , छत्तीसगढ़ ,झारखंड ,महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे 5राज्यों के 44आकांक्षी जिलों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं का प्रावधान किया गया था। परियोजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव अनुरोध)आरएफपी (दिनांक 07.12.2021को जारी किया गया है। कवर नहीं किए गए गांवों की राज्यवार सूची इस प्रकार है:

क्रमांक	राज्य का नाम	आकांक्षी जिलों की संख्या	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3	1218
2	छत्तीसगढ	8	699
3	झारखंड	19	827
4	महाराष्ट्र	4	610
5	ओडिशा	10	3933
	कुल	**44**	**7287**

36. अन्य आकांक्षी जिलों में सभी अनकवर्ड गांवों की पहचान करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में और सभी अनकवर्डगांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि विगत की अलग-अलग स्कीमों में अन्य आंकाक्षी जिलों के सेवा से वंचित गांवों को कवर किया गया था। इसके अलावा, देश में

सेवा से वंचित अन्य सभी गांवों के लिए स्कीम तैयार की जा रही है और इसमें अन्य राज्यों के आंकाक्षी जिलों के सेवा से वंचित शेष गांवों को भी कवर किया जाएगा।

37. समिति ने जारी आरएफपी की स्थिति के बारे में और इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा में भी पूछा । इसके उत्तर में विभाग ने कहा है कि आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित गांवों के लिए दिनांक 24.02.2022 को अनुरोध प्रस्ताव खोला गया था और दो बोलियां प्राप्त हुई है जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। समझौते पर अप्रैल, 2022 तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है जिसके पश्चात् यह परियोजना 18 माह में पूरी की जाएगी।

38. की गई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, एडमिनिस्ट्रेटर, यूएसओएफ ने निम्नानुसार कहा:

"जहां तक आकांक्षी जिलों का संबंध है**,** कवर न किए गए **502** गांवों के लिए कार्य सौंपा गया है। काम चल रहा है **20** से अधिक टावरों ने विकीर्ण करना शुरू कर दिया है बाकी टावर्स की स्थापना का कार्य चल रहा है। हाल ही में**,** हमें टावर लगाने के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त हुआ है और हम पांच राज्यों में आकांक्षी जिलों में 7**,**287 गांवों को कवर कर रहे हैं। निविदा का काम चल रहा है। शीघ्र ही**,** हम निविदा प्रदान करने और इन राज्यों में भी कार्य शुरू करने में सक्षम होंगे।**"**

(vii) <u>वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए योजना</u>

(क) <u>एलडब्ल्यूई चरण-I</u>

39. मंत्रिमंडल ने दिनांक 20-08-2014 को आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 10 प्रभावित राज्यों में 2जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में एक परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। परियोजना की अनुमोदित लागत 4214.28 करोड़ रुपये है। परियोजना पूरी कर ली गई है और इसका राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	**राज्य का नाम**	**एलडब्ल्यूई चरण-I**	
		वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुल जिले	**प्रचालित टावर**
1	आंध्र प्रदेश	8	62
2	बिहार	22	250
3	छत्तीसगढ़	16	525

क्रम संख्या	राज्य का नाम	एलडब्ल्यूई चरण-I	
		वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुल जिले	प्रचालित टावर
4	झारखंड	21	816
5	मध्य प्रदेश	1	22
6	महाराष्ट्र	4	65
7	ओडिशा	19	256
8	तेलंगाना	8	173
9	उत्तर प्रदेश	3	78
10	पश्चिम बंगाल	4	96
	कुल	**106**	**2343**

मौजूदा एलडब्ल्यूई-I साइटों का 4जी उन्नयन और विस्तार 2,426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विचाराधीन है।

(ख) <u>एलडब्ल्यूई चरण-II</u>

40. मंत्रिमंडल ने दिनांक 23.05.2018 को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 4072 स्थानों के लिए 7330 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता के साथ परियोजना के चरण-II के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आवश्यकताओं में संशोधन और स्थान में कमी के कारण बाद में 2,211.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु 2,542 टावरों के लिए परियोजना को अनुमोदित किया गया है।

तालिका: एलडब्ल्यूई चरण-II में मोबाइल टावरों की राज्य-वार सूची:

क्रम संख्या	राज्य	जिलों की संख्या	मोबाइल टावरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9	346
2	बिहार	7	16
3	छत्तीसगढ़	15	971
4	झारखंड	21	450
5	मध्य प्रदेश	2	23
6	महाराष्ट्र	3	125
7	ओडिशा	5	483

8	तेलंगाना	12	53
9	उत्तर प्रदेश	1	42
10	पश्चिम बंगाल	5	33
कुल		**80**	**2542**

41. उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने सूचित किया परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा जारी की गई थी और सितंबर/अक्टूबर 2021 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ 2211.11 करोड़ रुपये की लागत से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा (1602 टावर) और भारती एयरटेल लिमिटेड को आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (940 टावर) में परियोजना को लागू करना है। इस परियोजना को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

42. परियोजना को मार्च, 2023 तक पूरा करने के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि एलडब्ल्यूई-।। परियोजना सर्वेक्षण चरण में है और पहले से सर्वेक्षित साइटों के लिए कार्यान्वयन कार्य जारी है। विभाग की फील्ड यूनिट साप्ताहिक रिपोर्ट सहित परियोजना की प्रगति और परीक्षण और कमीशनिंग की निगरानी कर रही हैं। समय-तालिका के अनुसार कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के लिए परियोजना की गहन निगरानी की जा रही है।

43. एडमिनिस्ट्रेटर, यूएसओएफ ने साक्ष्य के दौरान आगे निम्नानुसार कहा:

> "महोदय, वामपंथी उग्रवाद के लिए दो चरण हैं। पहले चरण को बीएसएनएल द्वारा 2343 स्थलों के लिए कार्यान्वित किया गया था। यह परियोजना पूरी हो चुकी है। यह 2जी तकनीक से संबंधित था। अब इन्हें 4जी में अपग्रेड करने पर विचार किया जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद के चरण-II के मामले में, कार्य सौंप दिया गया है। टावरों का सर्वेक्षण और संस्थापना का कार्य प्रगति पर है। यह 2,500 अन्य स्थानों को कवर करता है।"

पांच. <u>रक्षा स्पेक्ट्रम :</u> रक्षा सेवाओं के लिए (ओएफसी) आधारित

44. समिति को बताया गया है कि नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना में रक्षा सेवाओं के लिए समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के लिए समर्पित और अत्याधुनिक संचार सुविधाएं सृजित करना है। परियोजना को पूरा करने में काफी देरी हुई है। मई 2018 में, सीसीईए ने परियोजना

की समयसीमा मई, 2020 निर्धारित की है । लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना में देरी हुई और सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2022 निर्धारित की है। एयरफोर्स एनएफएस को बीएसएनएल से लीज्ड लाइन सर्किट के साथ वर्ष 2012 में पूरा किया गया था।. फरवरी, 2022 में नेवी एनएफएस की सभी ग्रीनफील्ड साइट शुरू की गई हैं। एनएफएस परियोजना अतिरिक्त कवर प्रदान करेगी, संचार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाएगी और सेना के वर्तमान नेटवर्क की बाधाओं को दूर (रीडन्ड्रेंसी नेटवर्किंग में सुधार) किया जाएगा। इससे मिशन की महत्वपूर्ण क्षमताएं और रक्षा सेवाओं की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयारी सुदृढ़ होगी ।

45. प्रस्तावित, बीई, आरई, वास्तविक 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए प्रस्तावित और 2022-23 के लिए बीई निम्नानुसार हैं :

प्रस्तावित/ बजट अनुमान/संशोधित अनुमान /वास्तविक	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	5000	5000	10000	5440.20	1961
बजट अनुमान	4500	4705	5000	5200	1961
संशोधित अनुमान	2500	4705	4000	5200	-
वास्तविक	1927	4705	4000	3070 (जनवरी 2022 तक)	-
संशोधित अनुमान के संबंध में प्रतिशत	77%	100%	100%	59%	-

लगभग 97% ओएफसी बिछाया जा चुका है और 884 लिंक (कुल 924 लिंकों में से) चालू किए गए हैं। सभी घटकों के लिए खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में दिनाक 21.12.2021 को आयोजित समीक्षा बैठक में बीएसएनएल ने सूचित किया कि उसका मार्च 2022 तक सभी घटकों (यूएनएमएस को छोड़कर) को पूरा करने का लक्ष्य है। यूएनएमएस 13 इमारतों के निर्माण से जुड़ा हुआ है जिसमें देरी हो रही है और यह जून 2022 तक पूरा हो जाएगा।

46. योजना की प्रगति के संबंध में, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार प्रस्तुत किया :

"अब मैं रक्षा सेवाओं के लिए नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) की बात करूंगा। परियोजना के लिए प्रारंभिक संस्वीकृत लागत 13,334 करोड़ रुपये थी, जिसे अब संशोधित करके 24,664 करोड़ रुपये कर दिया गया है इसके दो प्रमुख घटक हैं - ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और उपकरण। ओएफसी के अंतर्गत, 60,000 किमी में से अखिल भारतीय आधार पर कुल मिलाकर, लगभग 58,300 किमी (97 प्रतिशत) बिछाया जा चुका है उपस्करों की सभी आठ घटक निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब तक, इस परियोजना के निष्पादन के लिए बीएसएनएल को 20,545 करोड़ रुपये (83 प्रतिशत) जारी किए गए हैं। इस परियोजना को मार्च, 2022 से यूएनएमएस (एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) घटक के बिना उत्तरोत्तर शुरू किए जाने की उम्मीद है, जिसके जून, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।"

47. सचिव दूर संचार विभाग ने विस्तार से निम्नवत बताया :

"यह एक अत्यधिक जटिल परियोजना है क्योंकि इसमें कुछ सबसे कठिन इलाकों में ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाना शामिल है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सशस्त्र बल संचालित होते हैं। नतीजतन, काम के लिए उपलब्ध विंडो बहुत सीमित हो गई है। यह एक मुद्दा है। दूसरा, कुछ इलाकों में विशेष रूप से चार धाम क्षेत्र में बहुत सारी निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। सड़क का काम चल रहा है। कई लिंक हैं जहां इस तथ्य के कारण काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है कि मार्ग का अधिकार उपलब्ध नहीं है क्योंकि मार्ग में कुछ अन्य काम पहले से ही प्रगति पर है।. इसलिए, कुछ लिंक में असफलताएं हुई हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लिंक को एक साथ आगे बढ़ा दिया गया है, और अब हम एक ऐसे चरण में हैं जब मुझे लगता है कि परीक्षण हो सकता है। कुछ संविदाओं में डाटा सेंटर आदि से संबंधित कुछ भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है। हमने पिछले तीन महीनों में दो विस्तृत समीक्षाएं की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे नेटवर्क से संबंधित कार्य, उन लिंकों को छोड़कर जिन्हें हम कार्य बल की उपलब्धता की कमी के कारण कमीशन करने में असमर्थ हैं, हम इसे जून तक पूरा करने में सक्षम होंगे। मेरे विचार से एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली से संबंधित शेष कार्य, हमें दिसंबर तक पूरा करने में सक्षम होंगे।"

48. विभाग ने यह भी सूचित किया कि पिछले डेढ़ वर्षों में अर्धचालकों की कमी एक और जटिल कारक रही है। कुछ उपकरण, जैसे राउटर आदि उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि सिस्को जैसी कंपनियां भी इसमें छह से आठ महीने की देरी कर रही हैं। इसने भी इसे बुरी तरह से प्रभावित किया है क्योंकि ये सभी ऑप्टिकल नेटवर्क उपकरण हैं जिन्हें उच्च अंत राउटर की आवश्यकता होती है।

49. बैठक के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के सीएमडी ने निम्नानुसार बताया:

> "महोदय, 924 लिंक्स को चालू किया जाना है, जिनमें से 877 लिंक्स पहले ही चालू किए जा चुके हैं। 18 संपर्क ऐसे हैं जो विभिन्न निर्माण कार्यों या सड़क संबंधी कार्य के कारण नहीं हो पा रहे हैं जो चल रहे हैं। केवल 19 लिंक्स लंबित है जिसे 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। इसी तरह, 42 नोड्स हैं जिसे नेवी के लिए शुरू किया जाना है; 22 नोड्स पहले ही शुरू किए गए हैं; और शेष 20 नोड्स अप्रैल माह तक शुरू किया जाना है। 1192 डीडब्ल्यूडीएम लिंक्स को शुरू किया जाना है जिसमें से 1163 पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। जीओएफएनएमएस के संबंध में 342 साइटों को शुरू किया जाना है जिसमें से 339 पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। यदि हम कार्य की प्रगति को देखें तो पाएंगे कि लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। हम लाग विभिन्न कमांडों में कार्य कर रहे हैं जिन्हें हैंडओवर किया जाना है। हमने जो पहला लक्ष्य निर्धारित किया है, वह दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र है जिसे सेना को 15 मार्च तक सौंपा जाना है। दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र का कार्य पूर्ण हो गया है। सेना को सौंपने के लिए केवल परीक्षण चल रहा है। इसलिए, दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र वह पहला भाग है जिसे हम कर रहे हैं। दूसरा भाग पश्चिमी क्षेत्र है जहां कार्य लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही साथ परीक्षण कार्य भी चल रहा है। हमारा उद्येश्य है कि हम प्रति माह एक कमांड सौंप सकें और इसके लिए हम जून तक पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो चीज बाधा उत्पन्न कर रही है, वह है यूएनएमएस भवन जो इस परियोजना का उपरी शीर्ष परत है अर्थात् एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली। प्रत्येक घटक में नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली है। यह एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली का शीर्ष परत है। भवन निर्माण में कुछ मामले थे। अब चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन डाटा केन्द्रों में सॉल्यूशन डिजायनिंग और अन्य बातें हो रही है ताकि तैनाती तेजी से की जा सके। इसलिए, मैं समिति के सदस्यों और सभापति को आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्य सही दिशा में बढ़ रहा है और लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

छः <u>दूरसंचार उपकरण का अनिवार्य परीक्षण</u>

50. दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन, घरेलू मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), विदेशी ओईएम और विदेशी ओईएम के अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) पर लागू होता है। किसी ऐसे टेलीग्राफ/दूरसंचार उपकरण, जिसके संबंध में अनिवार्य प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, का उपयोग दूरसंचार लाइसेंस धारक (पीएसयू अथवा निजी) द्वारा अपने नेटवर्क में तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अन्यथा प्रमाणित न किया गया हो । यह सत्य नहीं है कि टेस्टिंग केवल पीएसयू के लिए की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी टीएसपी दोनों को अधिसूचित होने पर, अपने नेटवर्क में प्रमाणित टेलीग्राफ/दूरसंचार उपकरण का ही उपयोग करना होगा। विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस) के तहत बेंगलुरु में एक संदर्भ सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला का उपयोग भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं (आईटीएसएआर) के विकास और दूरसंचार उपकरणों के लिए संबंधित परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (टीएसटीपी) की तैयारी के लिए किया जा रहा है। एनसीसीएस, देश में नामांकन(डेजिग्नेशन)/मान्यता हेतु, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में संभावित दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को नामांकित नहीं किया गया है/मान्यता नहीं दी गई है।

51. समिति ने जानना चाहा कि देश में किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की गैर मौजूदगी में दूरसंचार उपकरणों की जांच कैसे की जाती है इसके उत्तर में विभाग ने बताया कि संचार सुरक्षा (कॉमसेक) स्कीम को अनुमोदित और प्रकाशित कर दिया गया है। एनसीसीएस ने योजना की जानकारी देने के लिए संभावित दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के साथ मिलकरएक ओपन हाउस सत्र आयोजित किया है। दूरसंचार सुरक्षा रोडमैप तैयार किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा जो दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण चरणबद्ध रूप में प्रारम्भ करने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगा। "

52. सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए विभाग की योजना के बारे में विभाग ने कहा कि विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में एक सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला बनाने की योजना बनाई गई है। सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा दिनांक 20.12.21 को खोली गई थी जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। दो सुरक्षा उपकरणों, जिनके लिए उक्त निविदा में कोई पात्र बोलीदाता नहीं पाया गया है, की खरीद की प्रक्रिया जीईएम के माध्यम से शुरू की गई है। सुरक्षा परीक्षण उपकरण वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक खरीद लिए जाने की संभावनाहै।

53. विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार कहा:

> "अक्टूबर 2019 से, टीईसी ने दूरसंचार उपकरण योजना के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं के खिलाफ समनुरूपता परीक्षण और प्रमाणन शुरू किया। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2017 में प्रावधान है कि प्रत्येक दूरसंचार उपकरण को पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा।"

सात. <u>पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा</u>

(i) <u>बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई का कार्य निष्पादन</u>

54. बीएसएनएल के राजस्व एवं कार्यशील व्यय का विवरण निम्नलिखित है:

(**रुपए करोड़ में**)

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (अनुमानित)**	**2022-23 (अनुमानित)**
कुल आय का लक्ष्य	25000	20000	18000	एमयूओ लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है	एमयूओ लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है
कुल आय	19321	18907	18595	19000	20424
कुल व्यय	34225	34406	26036	27787	26410
निवल लाभ/हानि	-14904	-15500	-7441	-8787	-5986

55. पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के बावजूद वर्ष 2022-23 के लिए बीएसएनएल की अनुमानित निवल हानि 5986 करोड़ रुपये है। समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान एमटीएनएल की अनुमानित निवल हानिके बारे में पूछा और जानना चाहा कि बीएसएनएलऔर एमटीएनएल लाभ की स्थिति में कब होंगे, इसके उत्तर में विभाग ने कहा कि इस संबंध में होने वाला संभावित निवल घाटा मुख्य रूप से 4जी सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण है। ग्राहक,उच्च डेटा खपत के कारण 4जी सेवाओं का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि बीएसएनएल, ग्राहकों को ये सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है। अब लैंडलाइन राजस्व में भी पिछले कुछ समय से गिरावट आ रही है। चूंकि इस मामले में घरेलू 4जी उपकरण के लिए अवधाररणा के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) अंतिम चरणों में है, अत: नेटवर्क और सेवाओं का विस्तार इसके बाद होगा।इन कारणों को देखते हुएनए ग्राहकों को जोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण हो

गया है, इसी कारण से आगामी वित्तीय वर्ष (2022-23) में राजस्व में वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही है।हालांकि, यह उल्लेखनीयहै कि खर्च को कम करने के लिए लगातार किए गए प्रयासों की मदद से, बीएसएनएल सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही में ईबीआईटीडीए पॉजिटिवहो गया है, औरतब से पिछली 6 तिमाहियों से ऐसी स्थिति बनी हुई है।बीएसएनएल की, वर्ष 2025-26 में 4जी सेवाओं से राजस्व और भूमि मुद्रीकरण (लैंड मॉनिटाइजेशन) से प्राप्त होने वाली आय की मदद से पीएटी पॉजिटिव बन जाने की उम्मीद है।

56. एमटीएनएल का वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित निवल घाटा 3139.60 करोड़ रुपये है। हालांकि एमटीएनएल परिचालन लाभ बता रहा है। पिछली सात तिमाहियों से ईबीआईटीडीए पॉजिटिव है। ऋण ही अब इसके लिए एकमात्र चिंता का विषय है और एमटीएनएल को शुद्ध लाभ की स्थिति में लाने के लिए इस कठिनाई/चिंता को दूर करने की आवश्यकता है। एमटीएनएल परिसंपत्ति मुद्रीकरण को लागू कर रहा है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में ऋण को कम करने के मुख्य स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा एमटीएनएल को राजस्व का स्तर बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए कैपेक्स वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। वास्तविक समयसीमा इन दो सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

57. यह पूछे जाने पर कि वीआरएस ने राजस्व बचत में किस हद तक मदद की है**,** बीएसएनएल और एमटीएनएल के सीएमडी ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

> “बीएसएनएल पुनरुद्धार के व्यापक पहलू तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर थे। पहली बात तो यह कि 2019 में बीएसएनएल को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वह यह थी कि उसके पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसका राजस्व घट रहा था और कर्मचारियों की लागत बढ़ रही थी। आज किसी भी ऑपरेटर की कर्मचारी लागत 3-4 प्रतिशत से अधिक नहीं है, और बीएसएनएल के पास अपने राजस्व का 75-80 प्रतिशत था और वेतन बिल 15,000 करोड़ रुपये था। इसलिए, पहली समस्या का समाधान करने की आवश्यकता थी। तकनीकी परिवर्तन लैंडलाइन से मोबाइल में हुआ है जहां कम लोगों की आवश्यकता है। इसलिए निष्पक्ष तरीके से बीएसएनएल के कर्मचारियों को विदाई दी जा सकती है ताकि संगठन की कार्मिक संख्या कम की जा सके। अत: सरकार ने जो पहला कदम उठाया था वह वीआरएस लाना था। यह एक बहुत ही आकर्षक वीआरएस है जिसमें मूल वेतन का 125 प्रतिशत तक +

आईडीए का भुगतान किया गया है, जो अन्यथा उस वेतन के लिए देय होता जो लोगों ने आहरित किया होता। इसलिए, यह एक ऐसी योजना थी जिसमें सरकार ने विदा होने वाले कर्मचारियों पर लगभग 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसका लाभ बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ने लिया है। जनशक्ति में कमी के मामले में, आज, मेरा वेतन बिल 15,000 करोड़ रुपये की तुलना में 7,000 करोड़ रुपये है। अत, जहां तक बीएसएनएल का संबंध है, 8,000 करोड़ रुपये की बचत है, जो मैंने वीआरएस के कारण की है। अगर मुझे लगातार वह बोझ उठाना पड़ता तो मैं आज भी जीवित नहीं रह पाता। यदि आप ऐतिहासिक संख्याओं को देखें, तो जब बीएसएनएल को शामिल किया गया था, तब इसमें 3.6 लाख कर्मचारी थे। वीआरएस में कर्मचारियों की संख्या 1.55 लाख कर्मचारियों से कम हो गई है। आज मेरे पास 62,000 कर्मचारी हैं। इसलिए, यह सही दिशा में एक निर्णय था। फिर भी, यदि आप किसी भी ऑपरेटर को देखते हैं, तो किसी भी ऑपरेटर के पास 20,000 से अधिक कर्मचारी नहीं हैं। मेरे पास अभी भी 60,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कृपया इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखें। जियो की बाजार हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है; भारती की बाजार हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है; वोडाफोन की बाजार हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत है; और अभी भी उनके पास 20,000 से कम की जनशक्ति है जबकि नौ प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ मेरे पास 62,000 कर्मचारी हैं। इसलिए, यह सही दिशा में एक कदम था। क्या प्रबंधन ने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सही तरह की योजना बनाई है? हमने बहुत अच्छी योजना बनाई है, और मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कारण यह है कि एक भी दिन के लिए नेटवर्क नीचे नहीं था। जिस क्षण सरकार ने 23 अक्तूबर को निर्णय लिया, नवंबर और दिसम्बर से हमने प्रत्येक आदान-प्रदान के लिए योजना बनाई। हमारे पास 27,000 एक्सचेंज हैं और हमने प्रत्येक और हर एक्सचेंज के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई है कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाना है; इसका ध्यान कैसे रखा जाना चाहिए; और उस व्यक्ति का रिलीवर कौन होना चाहिए। कृपया इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक दिन में 1,55,000 कर्मचारियों में से मेरे पास केवल 65,000 कर्मचारी रह गए हैं। एक ही दिन में 60 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संगठन का प्रबंधन करना एक कठिन काम है."

58. जब समिति ने यह पूछा कि क्या कंपनी की आवश्यकता और वीआरएस लेने वालों के बीच कोई विसंगति है**,** तो विभाग ने प्रस्तुत किया कि बीएसएनएल के पास अभी भी पर्याप्त जनशक्ति है। यह पूछे जाने पर कि क्या वीआरएस प्रदान करने से पहले कोई कौशल की

पहचान की गई है, विभाग ने सूचित किया कि वीआरएस देते समय कोई कौशल सेट पहचान नहीं की गई है।

59. जब समिति ने अन्य स्रोतों से आय के बारे में जानना चाहा, तो प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

> "मुझे समिति के माननीय सदस्यों और सभापति को यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम केवल किराये की आय के रूप में 220 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करने जा रहे हैं। पिछले साल, हमारी आय 160 करोड़ रुपये थी। इसलिए हमने पट्टे पर देने के लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित की है। बीएसएनएल की प्रत्येक इकाई को पहले 25 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र की पहचान करनी होती है जिसे खाली किया जाना है। फिर, हमने इसकी सूची अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है कि ये वे क्षेत्र हैं जो उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी ले सकता है। ...xxxx.... हमारा लक्ष्य चार साल में 1000 करोड़ रुपये होना अर्जित करना है। हम उस राह पर हैं कि हर साल हमें किराये से कम से कम 100 करोड़ रुपये की कमाना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास टॉवर संपत्ति भी है। हम टॉवर को लेकर आक्रामक हो चले गए हैं। अब, 13,500 टावर विभिन्न निजी प्रचालकों के साथ-साथ सह-स्थान के आधार पर हैं, जिनमें मैं पास-थ्रू प्रभारों और किराये से हमें प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये अर्जित हो रहा हूं। इसलिए, किराये से आय लगभग 450 करोड़ रुपये है और पास-थ्रू शुल्क लगभग 550 करोड़ रुपये हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर को भी पट्टे पर दिया है जिसमें मुझे 400 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है जिसमें से 360 करोड़ रुपये बीबीएनएल से और 50 करोड़ रुपये निजी टीएसपी से मिल रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर परिसंपत्तियों से, जिसका हम अपने व्यवसाय के लिए लाभ उठा रहे हैं, हमें ऑप्टिकल फाइबर-नीत-व्यवसाय से 3500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा हूं। महोदय, यह सब बुरा नहीं है। मैं तथ्य भी रखना चाहूंगा। हमने कुछ व्यवसायों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।"

60. साक्ष्य के दौरान उन्होंने यह बताया कि:

> "जहां तक बीएसएनएल का संबंध है, फाइबर आधारित एफटीटीएच कनेक्शन तेजी से बढ़ रहा है और यह बीएसएनएल की सफलता की कहानी है। दो साल पहले हमारे पास पांच लाख कनेक्शन थे। पिछले साल हमने 12 लाख कनेक्शन बंद किए थे। इस साल हमने जनवरी के महीने में 21 लाख कनेक्शन के साथ बंद कर

दिया है। हम एफटीटीएच में लगभग एक लाख ग्राहकों को जोड़ रहे हैं जब सभी संसाधनों के साथ जियो 1.6 लाख जोड़ने में सक्षम है। जनवरी में हमने 1.14 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। कुछ स्थानों पर हमें अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर और सफलता हमें केवल इसलिए नहीं मिली है कि हमने केवल विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व वाली संरचना के पारंपरिक मोड का पालन किया है। हमने क्षेत्र स्तर पर सूक्ष्म उद्यमियों को शामिल किया है और उनके साथ राजस्व-साझाकरण व्यवस्था अपनाया है जहां बैकहॉल की सभी तकनीकी शक्तियां और स्टोरों की व्यवस्था बीएसएनएल द्वारा की जाती है, लेकिन ग्राहक परिदान सेवा और एक्सेस नेटवर्क निर्माण निजी लोगों द्वारा किया जाता है।''

(ii) <u>परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u>

61. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में विभाग ने सूचित किया कि बीएसएनएल के पास बड़ी संख्या में भूमि परिसंपत्तियों के साथ-साथ भवन भी हैं। अत, उनके पास दो-आयामी दृष्टिकोण है। सभी भूमि खंड जिसकी आवश्यकता नहीं है, की पहचान कर ली गई है और जो फ्रीहोल्ड संपत्ति है, उनकी एकमुश्त बिक्री के संदर्भ में मुद्रीकरण कर रहे हैं।

62. निर्धारित प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया :

"एक संहिताबद्ध प्रक्रिया है। शक्तियों और कार्य के प्रत्यायोजन के तीन तरीके हैं। वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित दीपम (डीआईपीएएम) के पास वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि है। 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच की परिसंपत्तियां बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार विभाग के माध्यम से की जाएंगी, और मंत्रियों का समूह इसे मंजूरी दी जाएगी। पहले से ही, लगभग ग्यारह परिसंपत्तियों पर कार्य विभिन्न चरणों में हैं। हमने हाल ही में बीएसएनएल की चार परिसंपत्तियों के लिए नीलामी की थी जिसमें से एक मध्यमग्राम में थी, दूसरी हैदराबाद में थी, तीसरी पंजाब के राजपुरा में थी और चौथी भावनगर गुजरात में थी। तीन मामलों में, बोली नहीं लगाई गई। एक मामले में बोली लगाई गई। लेकिन यह बोली तकनीकी रूप से अर्ह नहीं थी। इसलिए, प्रक्रिया को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और हम पूर्ण थ्रॉटल जा रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में पर्याप्त संसाधन उत्पन्न किए जाएंगे क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है और कोविड ने उन प्रक्रियाओं को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है क्योंकि पिछले डेढ़ साल से दो वर्षों में अचल संपत्ति वास्तव में बहुत कम हो गई है। पहला मुद्रीकरण है और दूसरा यह है कि हम अंतर्निहित परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के लिए बहुत जोर-शोर से काम कर रहे हैं।

63. सचिव, दूरसंचार विभाग ने निम्नवत बताया:

"महोदय, हमने डीडीए के साथ पिछले कई महीनों से बातचीत जारी रखी है। डीडीए परिसंपत्तियों के मामले में, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें 50 प्रतिशत आय उन्हें सौंपना होगा। यही हालत थी। इन भूमि का सशर्त आबंटन किया गया। वैसी भूमि जिनके टाइटल्स डीड क्लीयर है, बहुत कम हैं। वैसे भूमि का मुद्रीकरण किया जा रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में भूमि, बहुत महंगी भूमि ऐसी हैं जहां दो मुद्दे हैं। एक यह है कि जहां राज्य को लीजहोल्ड अधिकार मिला है क्योंकि वे बहुत पहले किए गए सशर्त असाइनमेंट किया गया था या उनका किसी विशेष उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया गया था। यह एक हिस्सा है। दूसरा भाग यह है कि मुंबई जैसे कुछ मामलों में उन्होंने कुछ आरक्षण की शर्तें लगाई हैं। उदाहरण के लिए, 75 प्रतिशत मेट्रो रेलवे शेड के लिए आरक्षित है। ये सभी भूमि के बड़े खंड हैं। अत उन्होंने कतिपय अव्यावहारिक शर्तें लगाए हैं। मैंने वहां के मुख्य सचिव से भी बात की है और हाल ही में हमारे राज्य मंत्री ने भी अपने शहरी विकास मंत्री के साथ बैठकें की हैं। हम वास्तव में उनसे उन शर्तों को छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में मूल्यांकन में तेजी से गिरावट आई है। मान लीजिए कि हम 75 प्रतिशत आरक्षण के साथ एक संपत्ति की नीलामी करने वाले थे, तो संपत्ति के मूल्य में गिरावट आएगी। यह इसका एक अंश होगा कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है और बाद में हमारे लिए समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, हम उन्हें इसे छोड़ने के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ प्रगति करने की उम्मीद करते हैं।''

(iii) <u>महानगर टेलीफोन लिमिटेड</u>

64. एमटीएनएल की कुल बकाया ऋण राशि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष के अंत में उधार राशियां				
				(राशि रु. करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	दीर्घावधि ऋण	सार्वभौम गारंटी बांड	ओवरड्राफ्ट/एसटीएल	कुल ऋण
2017-18	7654.60	2978.11	6382.09	17014.80
2018-19	9133.70	2978.45	7620.35	19732.50
2019-20	10690.34	2978.81	9296.42	22965.57
2020-21	10200.50	9474.18	5673.87	25348.55
2021-22 (31/12/2021 तक)	9764.00	9480.00	7221.00	26465.00

65. दिनांक28/02/2022 को एमटीएनएल का कुल बकाया ऋण26538.00 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के नोट में ऋण/ओवरड्राफ्ट/बांड के पुनर्भुगतान के लिए मुख्य योजना के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरणकी परिकल्पना की गईहै। दिनांक 28.02.2022 को परिसंपत्ति मुद्रीकरणकी स्थिति निम्नानुसार है:

- दो संपत्तियों के लिए ई-नीलामी अर्थात 20 ओशिवारा क्वार्टर और वसारी हिल पर लैंड पार्सल का कार्य पूरा हो गया है और नीलामी पर अंतर-मंत्रालयी समूह)आईएमजी (का निर्णय प्रक्रियाधीन है।
- मुंबई में एमटीएनएल की अधिकांश संपत्तियों में आरक्षण/पदनाम जैसे मुद्दे बने हुए हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि आवंटित एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा भूमि एक विशेष उद्देश्य/उपयोग के आवंटित की गई है जो इन संपत्तियों के मुद्रीकरण)मॉनिटाइजेशन(में बाधा बनी हुई है।एमटीएनएल आरक्षण/निर्धारण को हटाने के लिए यूडीडी, महाराष्ट्र और एमसीजीएम के साथ संपर्क कर प्रयास कर रहा है।मुद्दों के समाधान के लिए यूडीडी, एमएच और नगर नियोजन विभाग के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। इस संबंध में सीएमडी एमटीएनएल की ओर से प्रधान सचिव-I, यूडीडी महाराष्ट्र को पत्र दिनांक 06.12.2021के पत्र के माध्यम से अनुरोध भी भेजा गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार)आईपीसी (को378 क्वार्टरों के लिए नियुक्त किया गया था, रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यह दीपम) डीआईपीएएम(में प्रक्रियाधीन है।
- कनॉट प्लेस के लिए आईपीसी नियुक्त किया जा चुका है, संपत्ति का व्यवहार्यता संबंधीअध्ययन प्रक्रियाधीन है।
- एमटीएनएल वर्तमान परिदृश्य में अपनी अचल परिसंपत्तियोंके मूल्य का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से चिन्हित की गई 163 परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर रहा है।
- रोहिणी सेक्टर 8-और पंखा रोड प्लॉट)I और III) में से दो प्लॉटों का विकास/पुनर्विकास कार्यविचाराधीन है।

66. बैठक के दौरान एमटीएनएल, सीएमडी, बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों और ऋणों के बारे में पूछे जाने पर निम्नवत बताया गया :

> ''एमटीएनएल का कर्ज 26,000 करोड़ रुपये, राजस्व 1300 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान 2100 करोड़ रुपये है। महोदय, एमटीएनएल को तब तक वहनीय कंपनी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसके समस्याओं को समाधान करने के लिए बहुत बड़ा

हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। xxxx...." महोदय, परिसंपत्तियों की काफी अच्छी संख्या है। करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है। जब मैं 30,000 करोड़ रुपये कहता हूं, तो एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो दिल्ली में है या मुंबई में। दिल्ली में संपत्ति डीडीए द्वारा दी गई थी। यह बड़ा हिस्सा हैं। मुंबई में हमारे पास महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं लेकिन फिर से आपत्तियों और सुझाव का मुद्दा है। उन्हें अनब्लॉक करने की जरूरत है। जब तक नीतिगत बदलाव नहीं हो जाता तब तक अनलॉकिंग संभव नहीं होगी। इसलिए, हम इन मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं और सरकारी राजस्व या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शामिल किए बिना। सच कहूं तो, हम पाते हैं कि हम आईसीयू में हैं और किसी भी दिन इसे मृत घोषित किया जा सकता है या मैं कह सकता हूं कि एमटीएनएल में तबाही होने का इंतजार कर रही है।"

67. उन्होंने यह भी कहा:

''महोदय, एमटीएनएल की स्थिति दो पहलुओं के कारण इतनी खराब स्थिति में है। पहला है एमटीएनएल का कर्ज। यदि आप एमटीएनएल के 26,000 करोड़ रुपये का कर्ज को अलग रख सकते हैं, तो सभी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। मैं तथ्यों को आपके सामने वैसे ही रख रहा हूं जैसे वे हैं। 26,000 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ, भले ही भगवान पृथ्वी पर आकर इसकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, कंपनी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यह जीवन का एक तथ्य है; हमें इसे स्वीकार करना होगा। एकमात्र विकल्प इसे बंद करना है। अगर इसे बंद करना पड़ा तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नुकसान होगा। कोई समाधान उपलब्ध है। हमें इस पहलू में अधिक व्यावहारिक तरीके से देखना होगा। पहला, एमटीएनएल आज की तारीख में प्रचालनात्मक रूप से लाभदायक है क्योंकि जनशक्ति की संख्या में बहुत भारी कमी आई है और 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है। दूसरा, दिल्ली और मुंबई में होने के नाते, यह अपने कामकाज में स्थिति के बहुत ही बेहतर स्थिति में है। दिल्ली और मुंबई में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत अधिक है। मोबाइल बाजार में एमटीएनएल के लिए सफलता संभव नहीं है क्योंकि हर कोई रोमिंग प्रकार के परिदृश्य की तलाश करता है और यदि आप दिल्ली और मुंबई में दो द्वीपों पर हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। एमटीएनएल की परिसंपत्तियों को लेकर एक तरह से या दूसरे तरह से कर्ज को अलग करना चाहिए, और एयर इंडिया मॉडल की तरह कार्य करना चाहिए। आप स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) जैसे मॉडल बना सकते हैं जिसमें कर्ज और परिसंपत्ति को अलग करना चाहिए और इसके परिचालन को बीएसएनएल के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए। बीएसएनएल को इस वजह से फायदा होगा। आज, लीज लाइन और अन्य सेवाओं के लिए सभी उद्यम ग्राहक, एकल खिड़की अवधारणा पर

विश्वास करता है और बीएसएनएल के ग्राहक दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल सेवाओं की तरफ देखता है। एमटीएनएल की अनुपस्थिति में बीएसएनएल की प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होगी। दोनों कंपनियों का चेयरमैन होने के नाते, मैं इन दोनों कंपनियों को एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हूं जहां तालमेल बनाया जा सके। जहां उपकरणों को साझा किया जा रहा है, कोर नेटवर्क साझा किया जा रहा है, वहां बहुत सारे तालमेल बनाए गए हैं। अत, जो कुछ भी नियमों और विनियमों के भीतर किया जा सकता है, वह पहले से ही किया जा रहा है। लेकिन जब तक हम कर्ज के मुद्दे का समाधान नहीं करते हैं, तब तक एमटीएनएल का कोई भविष्य नहीं है।''

(iv) <u>बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पुनरुद्धार योजना</u>

68. सरकार ने दिनांक 23.10.2019 को बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार योजना को मंजूरी प्रदान की थी। पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से कर्मचारी लागत में कमी, बीएसएनएल/एमटीएनएल में सरकार द्वारा पूंजी निवेश के माध्यम से 4जी सेवाओं के लिए प्रशासनिक आवंटन, सॉवरेन गारंटी बांडों और बीएसएनएल / एमटीएनएल की संपत्ति को जुटाकर ऋण पुनर्गठन और मुद्रीकरण जैसे उपाय सम्मिलित हैं। पुनरुद्धार उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति और इसके प्रभाव निम्नानुसार हैं:

(i) बीएसएनएल और एमटीएनएल में वीआरएस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कुल 92910 कर्मचारियों ने वीआरएस प्रणाली के विकल्प का चयन किया है। इसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीएसएनएल में वेतन व्यय में लगभग 50% और एमटीएनएल में लगभग 80% की कमी आई है। इसके फलस्वरूप बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों वित्त वर्ष 2020-21 में ईबीआईडीटीए पॉजिटिव हो गए।

(ii) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमटीएनएल और बीएसएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने 4जी सेवाओं में अखिल भारतीय उपस्थिति के लिए बीएसएनएल को दिल्ली और मुंबई (एमटीएनएल क्षेत्रों) के स्पेक्ट्रम के आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार की आत्म-निर्भार अभियान के अंतर्गत बीएसएनएल ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) मार्ग के माध्यम से दिल्ली / मुंबई सहित क्षेत्रों के लिए आगामी 4जी निविदा में पंजीकरण-सह-भागीदारी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है। बोली लगाने वाले, पीओसी के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, बीएसएनएल के आगामी 4जी टेंडर में भाग लेने के पात्र हो जाएंगे। रुपये की राशि वित्त वर्ष 2022-23 में 4जी स्पेक्ट्रम की लागत के लिए 23,270 करोड़ (जीएसटी सहित) आवंटित किया गया है।

(iii) भूमि/भवन संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए डीआईपीएएम के चरण -1 में बीएसएनएल की 11 संपत्तियों (अस्थायी मूल्य 18,200 करोड़ रुपये) और एमटीएनएल की 6 संपत्तियों (अस्थायी मूल्य 5,158 करोड़ रुपये) के मुद्रीकरण को मंजूरी दी, जिसमें 4 बीएसएनएल की संपत्तियों (आरक्षित मूल्य 670 करोड़ रुपये) और एमटीएनएल की 2 संपत्तियों (290 करोड़ रुपये की आरक्षित कीमत) को ई-नीलामी के लिए लिया गया है। राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों से आवश्यक विभिन्न अनुमतियों के कारण अन्य संपत्तियों में चुनौतियां हैं, बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ जिनका विवरण किया जा रहा है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आय बीएसएनएल/एमटीएनएल को उनके ऋण, कैपेक्स और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा की जाएगी।

(IV) सरकार द्वारा दी गई सॉवरेन गारंटी की मदद से बीएसएनएल ने 8500 करोड़ रु और एमटीएनएल ने 6500 करोड़ रु के बांड के माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग मौजूदा उच्च लागत ऋण के पुनर्गठन के लिए किया गया है।

(v) सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को 'सैद्धांतिक' मंजूरी भी प्रदान की थी। एमटीएनएल पर अधिक कर्ज समेत वित्तीय कारणों से एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय टाल दिया गया है। हालांकि बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच घनिष्ठ सहयोग और सेवा एकीकरण किया गया है।

(vi) इसके अतिरिक्त सरकार ने सभी सरकारी विभाग/सीपीएसई/केंद्रीय स्वायत्त संगठन को इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन आवश्यकताओं के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्क के अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।

(v) <u>बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश</u>

69. पहले ही 4G सेवाओं को शुरू करने में चूक गया है और अच्छी वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने और अपने राजस्व में वृद्धि करने की क्षमता के मामले में पिछड़ गया है। उद्योग अब 5जी सेवाओं के लिए कमर कस रहा है और ट्राई ने 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया है। बीएसएनएल ने एक प्रमुख क्षेत्र में सहायता मांगी है। इसने अनुरोध किया है कि आगामी 5जी नीलामी में बीएसएनएल के लिए स्पेक्ट्रम को तीनों बैंडों- मिड-बैंड, सब-गीगाहर्ट्ज और एमएम वेव्स बैंड में आरक्षित किया जाना चाहिए।

70. बीएसएनएल द्वारा 4जी स्पेक्ट्रम शुरू करने की स्थिति के संबंध में समिति के प्रश्न के उत्तर में बिभाग ने कहा है कि *आत्मनिर्भर भारत'* पहल के अनुरूप बीएसएनएल ने दिनांक 1 जनवरी, 2021 को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है जिससे स्वदेशी निर्माताओं को पीओसी (सिधांत सिद्ध करना) में भाग लेकर अपने उत्पाद को तकनीकी रूप से साबित करने का अवसर मिलेगा। पीओसी के सफलतापूर्वक पूरा होनेपरबोलीदाता बीएसएनएल की आगामी 4जी निविदा में भाग लेने के पात्र हो जाएंगे। दिनांक 01.07.2021 को पाँच बोलीदाताओंअर्थात् मेसर्स एचएफसीएल, मैसर्सएलएंडटी, मैसर्सटेक महिंद्रा, मैसर्सटीसीएस और मैसर्सआईटीआईकोएलओआई जारी किया गया। एलओआई 01.07.2021 को पांच बोलीदाताओं अर्थात् मैसर्स एचएफसीएल, मैसर्स एल एंड टी, मैसर्स टेक महिंद्रा, मैसर्स टीसीएस और मैसर्स आईटीआई को जारी किया गया। मैसर्स टीसीएस और मैसर्स आईटीआई ने ईओआई के हिस्से के रूप में पीओसी के तहत परीक्षण के लिए अपने उपकरण तैनात किए हैं। प्रस्तावित उपकरणों का परीक्षण प्रगति पर है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैसर्स एचएफसीएल, मैसर्स एलएंडटी और मैसर्स टेक महिंद्रा के लिए पीओसी प्रक्रिया बंद है क्योंकि उन्होंने किसी भी उपकरण को तैनात नहीं किया है।

71. दूरसंचार विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया :

> ''हमारा मानना है कि जब तक व्यापार से संबंधित पुनर्गठन और सुधार पूंजी निवेश के माध्यम से नहीं किए जाते हैं, जाहिर है कि यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए, यह 4 जी निवेश एक अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। हमारा मानना है कि 4जी और 5जी में निवेश - 5जी में भी, सरकार ने पैकेज को अनुमोदित करते समय, 5जी से संबंधित निवेश के लिए प्रोत्साहन भी दिया है। इसलिए, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, इसे भी उठाया जाएगा क्योंकि अवधारणा के प्रमाण के अंतिम चरण में 4 जी उपकरण के बारे में 5 जी-सक्षम है। बहुत मामूली संशोधनों के साथ, वे 5 जी पर स्विच करने में सक्षम होंगे। वही स्पेक्ट्रम भी दिया जा सकता है। हमने बीएसएनएल से यह भी वादा किया था कि हम 5जी के लिए भी स्पैक्ट्रम आबंटित करेंगे। ये सभी के लिए भी उपलब्ध हैं, और शायद सी-बैंड, मिलीमीटर तरंग, आदि को छोड़कर 5 जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम निश्चित रूप से इस पर बीएसएनएल का समर्थन करेंगे।''

72. 4जी को लागू करने की समय-सीमा के बारे में दूरसंचार विभाग के सचिव ने बैठक के दौरान समिति को सूचित किया कि पीओसी मार्च में पूरा हो जाएगा। इसके बाद, लगभग छह महीने से एक वर्ष में वाणिज्यिक रोल आउट होने की उम्मीद है

(vi) <u>इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड</u>

73. आय और व्यय का विवरण निम्नवत दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***	**2022-23**
कुल आय लक्ष्य	3300	3300	2600	2723	
कुल आय	2005	2243	2523	604*	
कुल व्यय	1912	2095	2512	748*	
निवल लाभ/हानि	93	147	11	-144*	

*दिनांक30/09/2021 की स्थिति के अनुसार

74. 2021-22 के दौरान आईटीआई के शुद्ध नुकसान के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पूछे जाने पर, विभाग ने जवाब दिया है कि कार्यशील पूंजी की कमी, कोविड -19 महामारी के कारण लॉजिस्टिक बाधाएं, 2021-22 के दौरान 30.09.2021 तक आईटीआई के शुद्ध नुकसान के मुख्य कारण हैं। हालांकि, आईटीआई को वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद है क्योंकि उपलब्ध आदेशों को अधिकतम सीमा तक निष्पादित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, स्वदेशी विनिर्मित उत्पादों का उपयोग परियोजना आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा है जिससे उन्हें अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है

75. 2021-22 के दौरान, पूंजी अनुभाग के तहत आरई पर 80 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, हालांकि, उपयोग को 'शून्य' के रूप में दिखाया गया है। विभाग के अनुसार, आरई 2021-22 में 80 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 70 करोड़ रुपये को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आईटीआई को जारी करने के लिए 03/03/2022 को अनुमोदित किया गया है।

76. 400 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान आईटीआई को केवल 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 400 करोड़ रूपये की कैपेक्स राशि के लिए आईटीआई लिमिटेड द्वारा नियोजित परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	**परियोजनाओंका नाम**	**इकाई**	**बजटअनुमान 2022-23 रुपये करोड़में**
1	मोनो क्रिस्टलाइन सौर सेल	एनएनआई	125
2	डिजिटल मोबाइल रेडियो - डीएमआर	बीजीपी	15
3	पीसीबी प्लांट अपग्रेडेशन	बीजीपी	30
4	बैंगलोर, मनकापुर पलक्कड़में 4जीआरआरयू के लिए मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रा और टेस्ट सेटअप	बीजीपी/पीकेडी	58
5	एमएसपी/एसओसी की स्थापना	बीजीपी	20
6	राउटर निर्माण	बीजीपी	10
7	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-ईवीएम और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल-वीवीपी एटी मैन्युफैक्चरिंग	बीजीपी	10
8	बैंगलोर संयंत्र में ओएफसी विनिर्माण लाइन (प्रति वर्ष 30,000 की क्षमता)	बीजीपी	76
9	4जीबीबीयू मैन्युफैक्चरिंग	बीजीपी	56
	कुल		**400.00**

77 .उपरोक्त परियोजनाओं में से बजट अनुमान 2022-23 में200 करोड़ रुपये के तहत निम्नलिखित परियोजनाएँ कम केपेक्स राशि के साथ नियोजित की गई है।

क्र. सं.	**परियोजनाओंका नाम**	**इकाई**	**बजटअनुमान 2022-23 रुपये करोड़में**
1	मोनो क्रिस्टलाइन सौर सेल	एनएनआई	**100**
2	डिजिटल मोबाइल रेडियो - डीएमआर	बीजीपी	15
4	बैंगलोर, मनकापुर पलक्कड़में 4जीआरआरयू के लिए मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रा और टेस्ट सेटअप	बीजीपी/पीकेडी	58
7	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-ईवीएम और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल-वीवीपीएटीए मैन्युफैक्चरिंग ।	बीजीपी	10
9	4जीबीबीयू मैन्युफैक्चरिंग	बीजीपी	17
	कुल		**200.00**

78. समिति को सूचित किया गया है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार कुछ परियोजनाएं जिनके लिए केपेक्स कम किया गया है वे प्रभावित होंगी। हालांकि, आईटीआई लिमिटेड को वर्तमान में स्वीकृत 200 करोड़ रुपये के बजट अनुमान निधि के उपयोग के आधार पर संशोधित अनुमान के चरण में केपेक्स निधि की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी जिसे आईटीआई लि. को वर्तमान में स्वीकृत किया गया है।

(vii) <u>आईटीआई श्रीनगर इकाई</u>

79. श्रीनगर इकाई के पुनरूद्धार के लिए बनाई गई योजनाएं हैं : जम्मू और कश्मीर की भारतनेट परियोजनाओं के लिए आपूर्ति के लिए पीएलबी एचडीपीई डक्ट विनिर्माण संयंत्र की स्थापना, कैप्टिव उपयोग के लिए 60 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना जिससे बिजली के खर्च में कमी आएगी,ओएफसी बिछाने के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना जिसका उपयोग जम्मू-कश्मीर राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है,विपणन विंग की स्थापना: आईटीआई ने जम्मू-कश्मीर में आईटीआई उत्पादों के विपणन के लिए एक विपणन विंग स्थापित करने की योजना बनाई है। स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

80. जम्मू-कश्मीर की भारतनेट परियोजना के लिए आपूर्ति हेतुआईटीआई श्रीनगर में पीएलबी एचडीपीई डक्ट विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने श्रीनगर संयंत्र की साइट का दौरा किया है और पीएलबी एचडीपीई विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की मंजूरी का इंतजार है। भारतनेट की डिजिटल ग्राम परियोजना सहित स्थानीय परियोजनाओं की आवश्यकता के लिए एचडीपीई डक्ट की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी जिससे श्रीनगर संयंत्र के राजस्व में वृद्धि होगी। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए है कि दूरसंचार आयोग (अब डीसीसी) ने दिनांक 31/08/2018 को आयोजित अपनी 51 वीं बैठक में आईटीआई लिमिटेड की श्रीनगर इकाई को बंद करने का निदेश दिया था। चूंकि आईटीआई ने श्रीनगर इकाई को जारी रखने में रुचि व्यक्त की है इसलिए डीसीसी के विचार और अनुमोदन के लिए इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

भाग - दो

टिप्पणियाँ/सिफारिशें

दूरसंचार विभाग बजट

1. समिति नोट करती है कि दूरसंचार विभाग ने दिनांक 9 फरवरी, 2022 को 95547.80 करोड़ रुपए की कुल राशि की अनुदानों की मांगे (2022-23) रखी है जिनमें 32436.38 करोड़ रुपए राजस्व खंड और 63111.42 करोड़ रुपए पूंजी खंड के अंतर्गत हैं। यह राशि 2021-22 के ब.अ. स्तर पर किए गए आबंटन से 22610.8 करोड़ रुपए अधिक है। समिति नोट करती है कि पिछले वर्ष के क्रम में राजस्व खंड के अंतर्गत 9367.06 करोड़ रुपए की कमी आई है जबकि पूंजी खंड में 31977.86 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पूंजी खंड में वृद्धि मुख्यत: 'बीएसएनएल में पूंजी लगाया जाना' शीर्ष के अंतर्गत रही है। जहां तक उपयोग का संबंध है तो समिति नोट करती है कि राजस्व खंड के अंतर्गत ब.अ. स्तर पर ब.अ. 2021-22 स्तर पर 41803.44 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 38380.04 करोड़ रुपए की राशि आबंटित किया गया था और 28.02.2022 तक वास्तविक व्यय केवल 31547.03 करोड़ रुपए रहा है। राजस्व खंड के अंतर्गत सं.अ. स्तर पर निधियों के आबंटन में कमी मुख्यत: यूएसओएफ और 4जी स्पेक्ट्रम में जीएसटी के अनुदान के अंतर्गत रही है। वास्तव में, 4जी स्पेक्ट्रम में जीएसटी के अनुदान के अंतर्गत निधियों को ब.अ. स्तर पर 3647 करोड़ रुपए से लेकर सं.अ. स्तर पर शून्य तक घटा दिया गया है।

पूंजी खंड के अंतर्गत 2021-22 ब.अ. स्तर पर 31133.56 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 10670.17 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 28 फरवरी, 2022 को वास्तविक उपयोग केवल 6312.63 करोड़ रहा है जोकि सं.अ. स्तर पर किए गए आबंटन का मात्र 59.16 प्रतिशत है। ब.अ. स्तर पर 20410 करोड़ रुपए से सं.अ. स्तर पर 'शून्य' तक बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए पूंजी लगाया जाना, आईटी रिवाइवल हेतु इक्विटी इंफ्यूजन, वायरलेस सेट और उपस्कर (टीईसी), दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र (ओटीएससीसी) आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के मामले में निधियों का उपयोग और शून्य उपयोग किया जाना नोट किया गया है।

समिति नोट करती है कि सं.अ. के संदर्भ में 2021-22 के दौरान राजस्व और पूंजी खंड के अंतर्गत 28 फरवरी, 2022 के अनुसार निधियों का उपयोग क्रमश: 82.20 और 59.16 प्रतिशत रहा है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि राजस्व खंड के अंतर्गत 8300 करोड़ रुपए

के सं.अ. आबंटन के स्थान पर केवल 28 फरवरी, 2022 तक यूएसओएफ के अंतर्गत 3472.55 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि सं.अ. स्तर पर आबंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरा उपयोग कर किया जाएगा। समिति यह नोट करके भी परेशान है कि रक्षा सेवाओं हेतु ओएफसी नेटवर्क, टीईसी परियोजनाओं जैसी योजनाओं के अंतर्गत पूंजीखंड में निधियों का कम उपयोग हुआ है। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात 2021-22 के दौरान पूंजीखंड के अंतर्गत बीएसएनएल/एमटीएनएल में पूंजी लगाया जाना, आईटी रिवाइवल के इक्विटी इंफ्यूजन, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में निधियों का कम उपयोग है जिस पर विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक आत्मनिरीक्षण और इन योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि इन योजनाओं के मामले में क्या गलती हुई है। समिति नोट करती है कि 2022-23 से भारतनेट परियोजना को राजस्व से पूंजी खंड में अंतरित कर दिया गया है और ब.अ. 2022-23 स्तर पर 7000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। डिजिटल आसूचना एकक नामक नई योजना भी आरंभ की गई है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पूंजी के अंतर्गत ब.अ. 2022-23 में कुल 63111.42 आबंटित किए गए हैं, बीएसएनएल में पूंजी लगाने हेतु 44720 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। तथापि, उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत आबंटित राशि खर्च करने में असमर्थता चिंता का कारण बनी हुई है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विभाग ब.अ. 2021-22 में आबंटित 20410 करोड़ रुपए में से एक पैसा भी खर्च करने में असफल रहा है। समिति भारतनेट रक्षा सेवाओं हेतु ओएफसी नेटवर्क, आईडी रिवाइवल हेतु इक्विटी इंफ्यूजल, बीएसएनएल हेतु पूंजी लगाना, टीईसी परियोजनाओं, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत कम खर्च पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आशा करती है कि 2022 के दौरान उपयोग में सुधार आएगा तथा अगले वित्तीय वर्ष में कुछ उपर्युक्त योजनाओं में 'शून्य' उपयोग की पुनरावृत्ति नहीं होगी। समिति यह भी चाहती है कि उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निधियों के पर्याप्त आबंटन के लिए विभाग द्वारा पहले से समुचित उपाय किए जाएं ताकि पर्याप्त बजटीय सहायता के अभाव में कार्यान्वयन प्रभावित ना हो।

<u>सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)</u>

2. समिति नोट करती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अनुसार लाइसेंस के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5 प्रतिशत पर वसूल की जाती है। इसकी शुरुआत अर्थात् 2002-2003 से 1,21,827.84 करोड़ रुपए की राशि संग्रहीत की गई है और 62564.16 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार यूएसओ

के अंतर्गत संभावित निधि के रूप में यूएएल की उपलब्ध राशि 59,263.68 करोड़ रुपए है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि यूएएल के अंतर्गत संग्रहीत राशि भारत की संचित निधि में जाती है और यह स्वभावत: अव्यपगत होती है। तथापि समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि यद्यपि काफी राशि यूएसओएफ के अंतर्गत आरक्षित है। तथापि विभाग खर्च के मामले में बहुत कुछ नहीं कर पाया ताकि वह यूएसओएफ के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के लिए पात्र बना सके। 2021-22 के दौरान 13250 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के स्थान पर ब.अ. 2021-22 में 9000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 8300 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 21.02.2022 तक वास्तविक व्यय मात्र 3472.55 करोड़ रुपए था। यह निधियों के कम उपयोग की स्थिति को दर्शाता है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विभाग को उपयोग की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी रणनीतियों पर कार्य करने की आवश्यकता है। 2022-23 के लिए विभाग ने 9000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है और ब.अ. 2022-23 में इतनी ही राशि आबंटित की गई है। उनके पास पहले से ही प्राथमिक एवं चालू योजनाएं हैं जिनमें पूरे भारत में सभी 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के प्रावधान हेतु भारतनेट, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना को लक्षद्वीप तक सबमरीन केबल बिछाने के लिए द्वीप समूहों सहित व्यापक दूरसंचार विकास योजना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों के 354 गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं हेतु योजना तथा वामंपथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये अत्यधिक पूंजी गहन अवसंरचना परियोजनाएं हैं तो त्वरित और समय पर कार्यान्वयन इन क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने में काफी सहायता करेगा और अधिक से अधिक अनकवर्ड गांवों और दुर्गम क्षेत्रों को दूरसंचार क्रांति के दायरे में लाने में सहायता करेगा। समिति इस बात पर जोर देती है कि यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि की उपलब्धता की बाधा नहीं होनी चाहिए। इस बात पर विचार करते हुए कि यूएसओएफ के अंतर्गत संभावित निधि के रूप में पहले से ही काफी शेष राशि उपलब्ध है तो ब.अ. से सं.अ. स्तर पर निधि में कटौती की प्रवृत्ति को सख्त रूप से टाला जाना चाहिए। विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन पहले से प्राप्त आवश्यक है और उसे अपने व्यय की सीमा बढ़ाने तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को 2022-23 के दौरान यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु

ब.अ. स्तर पर आबंटित 9000 करोड़ रुपए के इष्टतम उपयोग के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

<u>भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति</u>

3. समिति नोट करती है कि भारतनेट विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन के साथ चरण-एक को दिसंबर, 2017 में पूरा किया गया था। चरण-दो कार्यान्वयाधीन है। विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से समिति नोट करती है कि दिनांक 31 जनवरी, 2022 को 30885.31 करोड़ रुपए की राशि उपयोग की गई है, 5,61,357 कि.मी. तक ओएफसी बिछाई गई है, 1,70,031 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है, 1,04,259 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट प्रदान किए गए हैं, 1,89,050 एफटीटीएच कनेक्शन दिए गए हैं, 34,514 कि.मी. डार्क फाइबर लीज पर लिए गए हैं आदि। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि डाटा कंजपशन का 5030 टीबी भी दर्ज किया गया है और आशा हे कि आगामी दिनों में इसमें वृद्धि होगी। राजस्व विभाजन के संबंध में बीएसपी के साथ अब तक 54 राजस्व विभाजन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और आशा है कि एफटीटीएच कनेक्शन के प्रावधान में निकट भविष्य में बढ़ोतरी होगी। समिति नोट करती है कि सेवा के लिए तैयार 65772 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पाट उपलब्ध कराए जाने हैं। समिति यह भी नोट करती है कि चरण-एक के अंतर्गत लगभग 1.10 लाख ग्राम पंचायतों, वाई-फाई सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने का कार्य सीएससीई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है और लगभग 10,000 ग्राम पंचायतों का कार्य राजस्थान सरकार को सौंपा गया है। सीएससी-एसपीबी को भी चरण-एक की 771115 ग्राम-पंचायतों में 5 सरकारी संस्थाओं के एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए वीजीएफ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण-दो में बिहार के 2692 ग्राम पंचायतों और 36744 गांवों में एक वाई-फाई और 5 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए सीएससी को भी कार्य सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94800 सरकारी संस्थानों अर्थात् विद्यालय, आंगनबाड़ी, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य ओर आरोग्य केंद्रों, डाकघरों आदि को सीएससी-एसपीवी द्वारा पहले ही कनेक्ट कर दिया गया है। चरण-दो के अंतर्गत राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल में भारतनेट का उपयोग राज्यों को सौंपा गया है। भारतनेट 8 राज्यों/संघ राज्यों की 16424 ग्राम पंचायतों को उनके स्थान का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त टिप्पणी से समिति नोट करती है कि सीएससी-एसपीवी को ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट देना और जीपी में सरकारी संस्थाओं को एफटीटीएच कनेक्शन का भारी कार्य दिया गया है। समिति का मत है कि सीएससी-एसपीवी के कार्यकरण की उचित निगरानी किए जाने की आवश्यकता है ताकि वह उन सभी जीपी में वाई-फाई सेवाओं एवं एफटीटीएच कनेक्शन देने में सक्षम हो सके जो उसे दी गई है। समिति ने पहले ही यूएसओएफ के अंतर्गत निधियों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया है जिसमें भारत नेट परियोजना प्रमुख परियोजनाओं में से है जिसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा योजनाओं की निधियों के उपयोग को बढ़ाने और और फेस-2 के अंतर्गत बनाए गए नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग/बीबीएनएल सेवा के लिए तैयार सभी जी.पी में वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयत्न करे। इस परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति की विस्तृत स्थिति के बारे में समिति को बताया जाए।

<u>6 लाख गांव को जोड़ने के लिए भारनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति</u>

4. समिति नोट करती है कि 30 जून, 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 16 राज्यों में सरकारी, निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन प्रणाली को अगस्त, 2023 तक मंजूरी दे दी। अब भारतनेट को सभी बसावट वाले गांवों तक ले जाने का प्रस्ताव किया गया है। ये 16 राज्य हैं-केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। प्रस्ताव के लिए अनुरोध 27.01.2022 को खोला गया, फिर भी, बोली पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2025 भारतनेट के एक भाग के रुप में संशोधित मॉडल तैयार किया जा रहा है। समिति को बताया गया है कि अनेक प्रणालियां, जैसे पीपीपी, राज्य चालित और सरकारी क्षेत्र द्वारा चालित देश के सभी गांव तक चरणों में पहुंचने के लिए स्वीकार की जाएगी। समिति यह नोट कर चिंतित है कि ऐसे कारणों जैसे आठ राज्यों (राज्य चालित मॉडल के अंतर्गत लगभग 65000 जीपी) और बीएसएनएल (सीपीएसयू चालित मॉडल में 23000 जीपी) जहां प्रगति धीमी रही है, से भारतनेट फेस-2 के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है। कोविड के प्रतिबंध, समय से संगत अनुमोदन और मंजूरी मिलने में विलंब, राज्यों द्वारा परियोजनाओं का घटिया कार्यान्वयन और बीएसएनएल के आंतरिक मुद्दों के कारण उसकी क्षमता संबंधी बाध्यताएं और वित्तीय स्थिति के कारण भी फेस-2 में प्रगति प्रभावित हुई है। समिति महसूस करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाए

जाने की अत्याश्यकता है क्योंकि लक्ष्य सभी बसावट वाले गांव अर्थात् 6 लाख गांव के अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने के लिए बढ़ा दिया गया है। बनाए गए नेटवर्क के अनुरक्षण तथा नेटवर्क के उपयोग में वृद्धि पर भी केंद्रीयकृत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि संशोधित मॉडल जो 16 राज्यों में पीपीपी के माध्यम से भारतनेट के लिए तैयार किया जा रहा है उसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन बिना किसी विलंब के आगे बढ़ सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अनेक परियोजनाएं जो सभी बसावट वाले गांव तक ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए विचाराधीन हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जाए और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी शीघ्र ली जाए। 2022-23 में हुई विस्तृत प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>महत्वाकांक्षी जिला योजना</u>

5. समिति नोट करती है कि चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में 502 कवर न किए गए गांव के लिए योजना को मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। समिति को आशा है कि परियोजना निर्धारित समय में पूरा हो जाएगी। समिति यह भी नोट करती है कि 7287 कवर न किए गए गांव के लिए योजना को कैबिनेट द्वारा 17 नवंबर, 2021 को मंजूरी दी गई जो 6566 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 महत्वाकांक्षी जिलों में 4जी आधारित मोबाईल सेवाओं का प्रावधान करने के लिए थी। समिति को बताया गया है कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध 24.02.2022 को खोला गया तथा 2 बोली प्राप्त हुई है और उसका मूल्यांकन हो रहा है। यह परियोजना समझौते पर संभवत: अप्रैल, 2022 तक हस्ताक्षर होने के बाद 18 महीने में पूरी होने का लक्ष्य है। समिति यह भी नोट करती है कि देश में सभी कवर न किए गए गांवों के लिए एक योजना तैयार की जा रही है तथा अन्य राज्यों के महत्वाकांक्षी जिलों में कवर न किए गए लंबित गांवों को ही कवर किया जाएगा।

समिति का मत है कि विभाग देश के सभी महत्वाकांक्षी जिलों के सभी कवर नहीं किए गए गांवों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें कवर करने के लक्ष्य से बहुत दूर है। यह महत्वपूर्ण है कि विभाग अत्यावश्यकता की भावना से कार्य करे और कार्य को निर्धारित समय में पूरा करे। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाएं और योजना के अनुसार अर्थात् नवंबर, 2023 तक 18 महीनों में 7287 कवर न किए गए गांवों को कवर करने का कार्य पूरा किया जाए। समिति यह भी इच्छा

व्यक्त करती है कि योजना जो सभी कवर न किए गए गांवों और केरल में वायनाड सहित अन्य राज्यों के महत्वाकांक्षी जिलों में कवर न किए गए लंबित गांवों के लिए तैयार की जा रही है उसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाए ताकि देश के सभी कवर न किए गए गांवों को समयबद्ध तरीके से अत्यावश्यक दूर संचार संपर्क प्रदान किया जाए।

<u>वामपंथ अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाईल संचार सेवा के लिए योजना</u>

6. समिति नोट करती है कि 106 जिलों में 2343 2-जी टॉवर की स्थापना करके बीएसएनल ने एलडब्ल्यूई फेस-1 का कार्यान्वयन किया था। 4-जी अपग्रेडेशन और मौजूदा एलडब्ल्यूई फेस-1 स्थलों के प्रसार का कार्य 2426 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ विचाराधीन है। समिति यह भी नोट करती है कि कैबिनेट ने 23.05.2018 को एलडब्ल्यूई फेस-2 परियोजना को मंजूरी दी थी। एलडब्ल्यूई फेस-2 के अंतर्गत 2542 4-जी टॉवर की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 2211.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना को मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। समिति को बताया गया है कि परियोजना के समयबद्ध रूप से पूरा होने के लिए निगरानी की जा रही है। वित्तीय आवंटन के बारे में समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

समिति का मत है कि एलडब्ल्यूई फेस टू परियोजना जिसे कैबिनेट द्वारा बहुत पहले 23 मई 2018 को मंजूरी दे दी गई थी, आवश्यकताओं के संशोधन में कमी बेशी होने के कारण तथा परियोजना के स्थान में कमी करने के कारण उसमें बहुत विलंब हुआ है। समिति महसूस करती है कि इन क्षेत्रों में 4जी सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान होने से लोगों को उनके घर पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने में बहुत सहायता मिलेगी तथा परियोजना के कार्यान्वयन में और विलंब होने से इन क्षेत्रों के लोगों की कनेक्टिविटी की समस्या बढ़ेगी ही। समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार प्रयत्न किए जाएं कि एलडब्ल्यूई फेस टू परियोजना मार्च 2023 तक पूरी हो जाए जैसा कि निर्धारित है। समिति यह भी महसूस करती है कि परियोजना की अनुमानित लागत 2211.11 करोड़ रुपए है इसलिए 2022 23 में 300 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन अत्यल्प और अपर्याप्त होगा । इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस योजना के अंतर्गत

निधियों का पर्याप्त आवंटन आवश्यक है । समिति यह भी सिफारिश करती है कि एल डब्ल्यू ई फेज वन के अंतर्गत 2343 2G टावर को 4G में उन्नयन करने की योजना जो विचाराधीन है उसे भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। समिति को इस योजना के अंतर्गत न केवल एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों बल्कि पूरे देश में हुई प्रगति तथा प्राप्त लक्ष्यों के बारे में सूचित किया जाए।

<u>डिफेंस स्पेक्ट्रम: रक्षा सेवाओं के लिए ओ एफ सी आधारित नेटवर्क</u>

7. समिति नोट करती है कि रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी नेटवर्क विभाग द्वारा लागू की जा रही अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। परियोजना के लिए प्रारंभिक स्वीकृत लागत 13334 करोड रुपए थी जिसे संशोधित करके अब 24664 करोड रुपए कर दिया गया है। समिति नोट करती है कि इस परियोजना के दो घटक हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) तथा उपकरण ओएफसी के अंतर्गत 60,000 किलोमीटर में से लगभग 58300 किलोमीटर अर्थात ओएफसी का 97 प्रतिशत बिछा दिया गया है। उपकरण के बारे में सभी आठों घटकों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं । समिति को यह भी बताया गया है कि आज तक 20545 करोड की धनराशि अर्थात 83% परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए बीएसएनल को जारी कर दी गई है। परियोजना के मार्च 2022 से यूएनएमएस (एसयूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम) के बिना प्रगतिशील रूप से शुरू किए जाने की आशा है और जिसे जून 2022 तक पूरा होने की आशा है। विभाग ने समिति को बताया है कि यह अत्यंत जटिल परियोजना है तथा इसमें अत्यंत कठिन क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना है। ऐसे अनेक लिंक हैं जहां राइट ऑफ वे ना होने से तथा अन्य कार्य जिन पर पहले से ही प्रगति हो रही है के कारण शुरू नहीं हो सका है। अब विभाग आशा करता है कि संपूर्ण नेटवर्क से संबंधित कार्य उन लिंक को छोड़कर जिन्हें कार्य बल उपलब्धता की कमी के कारण नहीं बनाया जा सकता है, जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि यह परियोजना ग्लोबल चिप की कमी के कारण भी प्रभावित हो रही है। यूएनएमएस से संबंधित शेष कार्य दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। कार्य के कमांड-वार प्रगति के बारे में समिति को बताया है कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे सेना को 15 मार्च 2022 तक दे दिया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र में भी कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा प्रति वर्ष एक कमांड को हैंडओवर करने की योजना है।

समिति नोट करती है कि स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस) परियोजना का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के लिए समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आधारित नेटवर्क प्रदान

करना है, जिसे बीएसएनएल द्वारा स्पेक्ट्रम जारी करने के बदले में कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, परियोजना आरओडब्ल्यू अनुमतियां प्राप्त करने में विलंब, पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कार्य मौसम, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवाजाही में प्रतिबंध आदि जैसे कारणों से अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। समिति यह भी नोट करती है कि वैश्विक चिप की कमी के कारण परियोजना को नुकसान हो रहा है। यद्यपि परियोजना में विलंब के लिए विभाग द्वारा उद्धृत कारण तर्कसंगत और वास्तविक प्रतीत होते हैं, परियोजना को चालू करने और रक्षा सेवाओं को उनकी ओएफसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें समर्पित करने में तात्कालिकता को संभवतः न्यूनतम या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। परियोजना के महत्व और अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि विभाग को उपरोक्त मुद्दों को रणनीतिक हस्तक्षेप के साथ समाधान करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परियोजना अपनी समय सीमा के अनुसार पूर्ण हो। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग/बीएसएनएल द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से पूरी हो ।

<u>दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण</u>

8. समिति नोट करती है कि दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) घरेलू मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम), विदेशी ओईएम और विदेशी ओईएम के प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) पर लागू होता है। कोई भी टेलीग्राफ/दूरसंचार उपकरण, जिसके संबंध में अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता होती है, का उपयोग अपने नेटवर्क में दूरसंचार लाइसेंस के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह पीएसयू हो या निजी, जब तक कि इसे प्रमाणित नहीं किया जाता है। तथापि, दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए सुरक्षा प्रयोगशाला के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट /प्रत्यायित नहीं किया गया है। कारण पूछे जाने पर, विभाग ने केवल यह उत्तर दिया है कि राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र देश में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में भावी दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। कुछ टीएसटीएल को 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान निर्दिष्ट किए जाने की संभावना है। विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया है कि दूरसंचार उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण के लिए संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना अभी शुरू की जानी है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में एक सुरक्षा परीक्षण

प्रयोगशाला की योजना बनाई गई है और सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा 20.12.2021 को खोली गई थी जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि दूरसंचार उपकरणों की आसान उपलब्धता के साथ बढ़ते दूरसंचार बाजार में सुरक्षा के खतरे बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं, फिर भी विभाग द्वारा दूरसंचार उपकरणों विशेष रूप से सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन से संबंधित, के अनिवार्य परीक्षण के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है । समिति यह नोट कर भी उतनी ही चिंतित है कि पिछले प्रतिवेदनों में इस मुद्दे पर उनके आग्रह के बावजूद देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट /प्रत्यायित नहीं किया गया है। दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार उपकरण और नेटवर्क स्पाइवेयर/मैलवेयर के लिए प्रवण हैं और सुरक्षा मुद्दों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समिति यह जानना चाहेगी कि देश में दूरसंचार उपकरणों की सुरक्षा जांच/प्रमाणन किस प्रकार किया जा रहा है। विभाग समिति को यह भी सूचित करे कि विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव कब से लंबित है और अब तक सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं। समिति सिफारिश करती है कि सुरक्षा जांच प्रयोगशाला की स्थपना की प्रारंभिक रूपरेखा शीघ्र बनाई जाती है। समिति यह भी चाहती है कि देश में सुरक्षा जांच प्रयोगशालाओं सहित अत्याधुनिक जांच सुविधाओं की स्थापना के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएं। समिति चाहती है कि तैयार की जा रही संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना का ब्यौरा समिति को प्रस्तुत किया जाए। जब तक संस्थागत व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं, तब तक समिति विभाग को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि दूरसंचार उपकरणों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और सभी सार्वजनिक और निजी दोनों दूरसंचार ऑपरेटर केवल उन उपकरणों को सख्ती से तैनात करें, जिनका अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन किया गया है।

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा</u>

<u>भारत संचार निगम लिमिटेड</u>

9. समिति नोट करती है कि 2022-23 के दौरान बीएसएनएल का अनुमानित शुद्ध घाटा 5986 करोड़ रुपये है। यह विभाग द्वारा बीएसएनएल की पुनरुद्धार योजना लागू किए जाने के बावजूद है। समिति को सूचित किया गया है कि पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल में वीआरएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल में वेतन व्यय में लगभग 50 प्रतिशत और एमटीएनएल में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि, विभाग ने समिति को सूचित किया है कि बीएसएनएल की अनुमानित निवल हानि मुख्यरूप से 4जी सेवाओं की अनुपस्थिति के कारण है। लैंडलाइन राजस्व भी हाल ही में घटा है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि कैपेक्स के लिए निधियों की अनुपलब्धता ने नेटवर्क और सेवाओं के विस्तार को प्रभावित किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि उपर्युक्त कारकों के कारण बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से बाधित हुई है, जिसके वर्ष 2022-23 में जारी रहने की संभावना है, साथ ही वर्ष 2022-23 में बीएसएनएल द्वारा राजस्व में भारी वृद्धि दूर होना कठिन लगता है। बीएसएनएल के 4जी सेवाओं से प्राप्त राजस्व और भूमि मुद्रीकरण से होने वाली आय की मदद से वर्ष 2025-26 तक ही पीएटी पॉजिटिव होने की उम्मीद है। जबकि बीएसएनएल के लिए 4जी को अभी शुरू किया जाना है, समिति ने नोट किया है कि कंपनी अन्य स्रोतों से राजस्व अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 2021-22 के दौरान किराये की आय से अनुमानित राजस्व आय 2019-20 में 160 करोड़ रुपये की तुलना में 220 करोड़ रुपये है। बीएसएनएल की योजना किराये की आय से अधिक राजस्व जोड़ने की है। बीएसएनएल के 13,500 टावरों को भी शेयरिंग के आधार पर लगाया गया है और बीएसएनएल को प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये की आय हो रही है। बीएसएनएल ने ऑप्टिकल फाइबर को भी पट्टे पर दिया है जिसके लिए कंपनी को 400 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि फाइबर आधारित एफटीटीएच कनेक्शन बीएसएनएल की वृद्धि और सफलता का आधार है। जनवरी, 2021 तक, बीएसएनएल के पास 21 लाख एफटीटीएच कनेक्शन हैं।

समिति नोट करती है कि वीआरएस के कार्यान्वयन से बीएसएनएल के वेतन व्यय में भारी कमी आई है। तथापि, आने वाले वर्षों में बीएसएनएल के अनुमानित घाटे को कम करने के लिए अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समिति को यह बताया गया है कि संगठन में कौशल आवश्यकता की पहचान के लिए किसी भी महत्वपूर्ण मूल्यांकन के बिना पूरे संगठन में वीआरएस लागू किया गया है। समिति को डर है कि वीआरएस वास्तव में कंपनी की राजस्व आय के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की कमी का कारण बन सकता है। समिति को इस बात की खुशी है कि बीएसएनएल में अभी तक सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कंपनी राजस्व अर्जित करने की कोशिश कर रही है। समिति उपर्युक्त उपायों की सराहना करते हुए यह सिफारिश करती है कि

विभाग/बीएसएनएल राजस्व अर्जन की संभावनाओं का पूरी तरह से पता लगाने के लिए अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखेगा और सभी उपलब्ध बचतों अर्थात् किराये की आय, टावर परिसंपत्तियों में भागीदारी, फाइबर को पट्टे पर देना, एफटीटीएच कनेक्शन आदि से अपनी राजस्व आय में वृद्धि करना जारी रखेगा। समिति को इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि से अवगत कराया जाए, जिसमें परिसंपत्तियों की नीलामी, जो हो सकती है, से होने वाली आय भी शामिल है।

<u>बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u>

10. समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल के पास बड़ी संख्या में भूमि परिसंपत्तियों सहित भवन भी हैं। एमटीएनएल के पास करीब 30,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है। केंद्रीय कैबिनेट नोट में ऋण/ओवरड्राफ्ट/बांड के पुनर्भुगतान के लिए मुख्य योजना के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की परिकल्पना की गई है। संहिताबद्ध प्रक्रिया के संबंध में, समिति ने नोट किया है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परिसंपत्ति के लिए अनुमोदन डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय के पास है। 10-100 करोड़ रुपये के मध्य की परिसंपत्तियां बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार विभाग के माध्यम से की जाएंगी और मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। 10 करोड़ रुपये से कम की परिसंपत्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी बीएसएनएल निदेशक मंडल है। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि भूमि/भवन के मुद्रीकरण के लिए डीआईपीएएम ने चरण-I में बीएसएनएल की परिसंपत्तियों (संभावित मूल्य 18,200 करोड़ रुपये) और एमटीएनएल की 6 परिसंपत्तियों (संभावित मूल्य 5158 करोड़ रुपये) के मुद्रीकरण को मंजूरी दी थी, जिसमें से बीएसएनएल की 4 संपत्तियों (670 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य) और एमटीएनएल की 2 संपत्तियों (290 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य) को ई-नीलामी के लिए लिया गया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि काफी समय पहले किए गए सशर्त कार्यों और राज्य सरकारों अथवा स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमतियों के कारण अन्य संपत्तियों में चुनौतियां/बाधाएं हैं, जिनका विभाग द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ-साथ अवलोकन किया जा रहा है। एमटीएनएल के संबंध में, समिति ने नोट किया है कि मुंबई में अधिकांश परिसंपत्तियों में आरक्षण/मनोयन के मुद्दे हैं और इससे इन संपत्तियों के मुद्रीकरण की संभावना बाधित हो रही है। एमटीएनएल आरक्षण/ मनोयन को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ कार्रवाई कर रहा है। समिति को बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह भी सूचित किया गया है कि मुंबई में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को लेकर आपत्ति और चिन्हित किए जाने के मुद्दे हैं जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर परिस्थितियों

के कारण संपत्ति का मूल्यांकन कम हो रहा है और यह नीति में बदलाव किए बिना संभव नहीं होगा।

समिति का मत है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों का लाभ पूर्ण उपयोग तथा संपत्तियों के मुद्रीकरण से सृजित आय को वस्तुत उनके कर्ज, कैपेक्स और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। समिति का मानना है कि संपत्तियों के सफल मुद्रीकरण से सरकार के राजस्व या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उपयोग के बिना दोनों कंपनियों के पुनर्जीवन प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। समिति नोट करती है कि विभाग/बीएसएनएल ने संपत्तियों के सौहार्दपूर्ण समाधान और सफल मुद्रीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ आपत्तियों और सुझावों के मुद्दे पर चर्चा की है। तथापि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। समिति का सुविचारित मत है कि ये संपत्तियां जो अप्रयुक्त पड़ी है, का सफल उपयोग बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिए तथा संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के बेहतर हित में होगा और इसलिए इस मामले को केवल विभाग/बीएसएनएल पर छोड़ने के बजाय नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया जाए।

<u>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड</u>

11. समिति नोट करती है कि वर्ष 2022 23 मई एमटीएनएल का अनुमानित शुद्ध घाटा 3139.60 करोड़ों रुपए है। समिति नोट करती है कि 28 फरवरी 2022 तक एमटीएनएल की बकाया कर्ज 26538 करोड़ों रुपए है। बैठक के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के सीएमडी ने समिति को स्पष्ट रूप से बताया कि एमटीएनएल को तब तक चलने वाली कंपनी नहीं बनाया जा सकता जब तक इस की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ा हस्तक्षेप ना किया जाए। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि यदि एमटीएनएल के बकाया कर्ज को एक तरफ रख दिया जाए तभी इसकी सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अपने वर्तमान स्थिति में एमटीएनएल बिल्कुल भी चलने योग्य कंपनी नहीं है, तथापि एमटीएनएल को बंद करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। घूमने सिद्धा दिया है कि एक संभव उपाय और व्यवहारिक अदम्य हो सकता है कि स्पेशल परपस वेहिकल (एसपीवी) बनाकर इसके कर्ज और संपति के मामले को देखना चाहिए और परिचालन संबंधी कार्य को बीएसएनएल में विलय कर देना चाहिए और विराम उन्होंने यह भी बताया कि इससे बीएसएनएल को भी लाभ होगा। समिति को यह भी सूचित किया गया कि बीएसएनएल और

एमटीएनएल के बीच संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयास होनी चाहिए और इन दोनों कंपनियों के बीच पहले से ही काफी संबंध स्थापित किए जा चुके हैं जहां उपकरण, कोडों आदि का आदान प्रदान किया जा रहा है।

समिति एमटीएनएल की कठिन स्थिति से पूरी तरह अवगत है। समिति का दृढ़ मत है कि जहां तक एमटीएनएल का संबंध है इसके मामले पर हमेशा से उतार-चढ़ाव रहा है और एमटीएनएल के भविष्य पर तत्काल निर्णय लिए जाने की जरूरत है। समिति मानती है कि वर्तमान स्थिति में पहले की तरह एमटीएनएल के व्यवसाय को जारी रखना केवल करदाताओं के धन का दुरुपयोग होगा और इसे यथाशीघ्र रोका जाना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि एयर इंडिया की तरह इसके कर्ज और संपत्ति के बारे में विचार करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विभाग को विचार करना चाहिए और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के सीएमडी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इसके परिचालन को बीएसएनएल के साथ विलय करना चाहिए एवं एमटीएनएल के भविष्य से संबंधित कुछ व्यवहार्य प्रस्ताव लाने चाहिए। समिति इस तथ्य से भी अवगत है कि एमटीएनएल को बंद करने पर लिए गए कोई भी निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

<u>बीएसएनएल के लिए पूंजी निवेश</u>

12. समिति नोट करती है कि विभिन्न पुनर्जीवन उपाय के क्रियान्वयन के लिए 2022-23 के दौरान बजट अनुमान 2022-23 में 44720 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समिति को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4जी स्पेक्ट्रम की लागत के लिए 23270 करोड रुपए (जीएसटी सहित) आवंटित की गई है। विभाग ने समिति को बताया है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के तर्ज पर बीएसएनएल ने 1 जनवरी 2021 को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति पांच बोलीदाताओं नामत: मेसर्स एचएफसीएल, मेसर्स टेक महिंद्रा, मेसर्स टीसीएस और मेसर्स आईटीआई को जारी किया गया है। केवल मेसर्स टीसीएस और मेसर्स आईटीआई ने अभिरुचि की अभिव्यक्ति के भाग के रूप में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट (पीओसी) के तहत परीक्षण हेतु अपने उपकरण विकसित किए हैं। समिति को बताया गया है कि दिए गए उपकरण का परीक्षण किया जा रहा है और मार्च तक पीयूसी पूरा होगा। इसके बाद इसका व्यवसायिक आरंभ लगभग 6 माह से 1 वर्ष में होने का अनुमान है। समिति को यदि बताया गया है कि पुनर्जीवन पैकेज अनुमोदित करते समय सरकार ने 5जी संबंधित निवेश के लिए प्रोत्साहन भी दिया है और 4जी उपकरण, जो अंतिम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के अंतिम चरण में है, 5जी सक्षम भी है।

समिति का विचार है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाओं के आरंभ से बीएसएनएल को न केवल देश में दूरसंचार क्षेत्र में अपना पैर जमाने में मजबूती और साथ ही इसके राजस्व में भी वृद्धि में बहुत सहायक होगा। यह देखना दुख की बात है कि बीएसएनएल पहले ही 4जी सेवा शुरू करने में असफल रही है और एक अच्छी बेतार ब्रॉडबैंड सेवाएं देने और इसके राजस्व वृद्धि की क्षमता प्रभावित हुई है। समिति को भी टिप्पणी करना पड़ रहा है कि बीएसएनएल को निजी या विदेशी कंपनियों से उपकरण लेने की अनुमति नहीं दी गई जबकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसा करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, निजी प्रचालकों की तुलना में बीएसएनएल को समान अवसर नहीं दिया गया। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को नियत समय सीमा अर्थात मार्च, 2022 तक पूरा किया जाना चाहिए और समिति को सूचित किए गए अनुसार बीएसएनएल द्वारा लगभग 6 माह से 1 वर्ष में 4जी सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए विभाग को सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी से कंपनी के अस्तित्व और उद्योग में फलने-फूलने के संघर्ष की संभावनाओं को और नुकसान होगा। समिति पूजा भी सिफारिश करती है कि बीएसएनएल को सभी बैंडों में 5जी स्पेक्ट्रम भी आवंटित की जानी चाहिए ताकि बीएसएनल निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ 5जी सेवाएं शुरू कर सके। यह आवश्यक है कि बीएसएनएल को 5जी सेवाएं शुरू करने और निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरह उपकरण खरीदने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। समिति चाहती है कि इस संबंध में इमानदारी पूर्वक प्रयास किए जाए और आशा करती है कि साक्ष्य के दौरान समिति को दिए गए आश्वासन अक्षरश: पूर्ण करेंगी।

<u>भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड</u>

13. समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान आईटीआई की कुल आय 2243 करोड़ रुपए थी और शुद्ध लाभ 147 करोड रुपए था जिसमें 85.40 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान शामिल है। 2020-21 के दौरान कुल आय 2523 करोड़ रुपए थी और शुद्ध लाभ 11 करोड़ रुपए था। 2021-22 के दौरान 30 सितंबर, 2021 तक कुल शुद्ध घाटा 144 करोड रुपए था। विभाग में 2021-22 के दौरान आईटीआई के शुद्ध घाटा का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी की वजह से कार्यकारी पूंजी की कमी, लॉजिस्टिक कमी, आदि बताया है। तथापि आईटीआई को आशा है कि वह वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर लेगा और उपलब्ध ऑर्डरों को अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। इसके साथ परियोजना की जरूरतों के लिए अपने निर्मित उत्पादों का उपयोग कर रही है जिससे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। समिति को यह भी बताया गया है कि

आईटीआई दो परियोजनाएं नामत: महानेट और गुजनेट कर रही है। गुजनेट का कार्य पूरा हो गया है जिससे आईटीआई को लाभ हो रहा है जबकि महानेट का लाभ मार्जिन कम रहा है और इसे बुक नहीं किया गया है। तथापि कंपनी अभी भी लाभ की स्थिति में है। पूंजीगत व्यय के संबंध में समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2021-22 में 80 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर शून्य कर दिया गया है। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि सक्षम प्राधिकारी ने आईटीआई को जारी करने के लिए 3 मार्च, 2022 को 70 करोड रुपए अनुमोदित की है। 2022-23 के लिए 400 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में केवल 200 करोड़ रुपए आवंटित की गई है।

समिति का मत है कि आईटीआई लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार उपक्रम देश की घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को प्रोत्साहन देने में केंद्रीय भूमिका निभा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल में सरकार दूरसंचार उपकरण सहित हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के स्वदेशी निर्माण को बहुत ज्यादा महत्व और जोर दे रही है, विभाग को कंपनी के कायाकल्प की गति को बनाए रखने और आईटीआई को सभी सहायता देने की जरूरत है ताकि यह देश में दूरसंचार उपकरण के घरेलू विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। समिति सिफारिश करती है कि आईटीआई को पर्याप्त पूंजी का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ा सके वरन साथ ही नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिकी से स्वयं को सुसज्जित और 5जी उपकरण सहित नवीनतम उत्पाद का भी निर्माण करने में भी सक्षम हो सके। समिति इसे दुर्भाग्य मानती है कि 2021-22 के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने 70 करोड रुपए के पूंजीगत व्यय का अनुमोदन 3 मार्च, 2022 को दिया। 2022-23 के दौरान भी 400 करोड रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में केवल 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जब तक इसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए कंपनी के कुछ संपत्तियों का मुद्रीकरण करना संभव नहीं होता तब तक निश्चित रूप से यह कंपनी की परियोजना कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित होगी। जटिल दूरसंचार परिवेश मे बाजार व्यवहार्यता को उचित सम्मान देते हुए सतत प्रयास जारी रखने से कंपनी के संपूर्ण कायाकल्प करने में सहायता मिलेगी और आने वाले वर्षों में राजस्व आय में वृद्धि होगी।

आईटीआई श्रीनगर इकाई

14. समिति को बताया गया है कि श्रीनगर की आईटीआई इकाई के लिए कई प्रकार के क्रियाकलापों की योजना बनाई गई है जिसमें भारतनेट परियोजना के लिए आपूर्ति हेतु पीएलबी एचडीपीई डक्ट के विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करना, आदि शामिल है। समिति को बताया गया है कि इससे श्रीनगर इकाई के राजस्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी। समिति नोट करती है कि जम्मू व कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने श्रीनगर संयंत्र स्थल का दौरा किया है और पीएलबी एचडीपीई विनिर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु जम्मू व कश्मीर सरकार का अनुमोदन मिलना है। विभाग ने समिति को बताया है कि दूरसंचार आयोग (अब डीसीसी) ने 31 अगस्त, 2018 को हुई अपनी बैठक में आईटीआई की श्रीनगर इकाई को बंद करने का निर्देश दिया था लेकिन चूंकि आईटीआई ने श्रीनगर इकाई को जारी रखें रुचि व्यक्त की है, इसलिए आईटीआई को डीसीसी के विचार और अनुमोदन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति चाहती है कि विभाग इस मामले को जम्मू व कश्मीर सरकार के साथ पूरी ईमानदारी से उठाएं और उनसे पीएलबी एचडीपीई विनिर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु अपना अनुमोदन देने के लिए अनुरोध किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि आईटीआई श्रीनगर इकाई के लिए उपयुक्त रूप से भावी रूपरेखा बताते हुए इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव आईटीआई द्वारा बनाई जाए और डीसीसी के विचार और अनुमोदन हेतु उसे प्रस्तुत किया जाए।

नई दिल्ली; **डॉ .शशि थरूर**

16 मार्च, 2022 **सभापति,**

25 फाल्गुन, 1943 (शक(**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**